

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. P.J. KURIEN): Shri Vijay Darda to move a Resolution urging upon the Government to take urgent steps to increase the power generation in the country.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

Need to increase power generation in the country

श्री विजय जवाहरलाल दडा (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूँ:-

"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि-

i. विद्युत/ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी भारत के भावी सामाजिक-आर्थिक पुनरुत्थान की गति को धीमा कर रही है और समाप्त होते जा रहे जल तथा लिग्नाइट/कोयला संसाधनों के कारण विद्युत उत्पादन से संबंधित समस्याएं आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं;

ii. विद्युत-उत्पादन के सौर ऊर्जा-स्रोत और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रारम्भिक अवस्था में हैं और वाणिज्यिक उपयोग के लिए इनका दोहन तथा राष्ट्रीय ग्रिड में इनका कोई मात्रात्मक योगदान नगण्य है;

iii. परमाणु रिएक्टरों से बहुत कम मात्रा में विद्युत प्राप्त होती है, हालांकि, गत वर्ष भारत-अमरीका परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने से तथा उसके बाद अनेक अन्य देशों के साथ इसी प्रकार के समझौते किए जाने से वर्तमान में स्थापित तथा भविष्य में स्थापित किए जाने वाले रिएक्टरों को चलाने के लिए हमें परमाणु ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति होने की स्थिति में विद्युत-उत्पादन में बढ़ोत्तरी की उम्मीद है।

iv. अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तुलना में विद्युत के पारेषण और संवितरण में होने वाली हानि बहुत अधिक है।

v. राज्य विद्युत बोर्डों की ओर भारी मात्रा में धन राशि बकाया है और उनके द्वारा राष्ट्रीय ग्रिड से, अपने नियत कोटे से अधिक मात्रा में बेरोकटोक विद्युत लिए जाने से विद्युत की निराशाजनक स्थिति और भी बदतर हो जाती है।

vi. विद्युत-उत्पादन पूंजी प्रधान क्षेत्र है और इसकी उत्पादन-पूर्व-तैयारी अवधि काफी लम्बी होती है; और

vii. छोटे और सीमांत किसानों को अपने पम्प सेटों को चलाने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे तथा कुटीर/खादी उद्योगों की इकाइयों को आसानी से विद्युत उपलब्ध कराना एवं यंत्रचालित कृषि के माध्यम से अधिकाधिक कृषि उत्पादन की प्राप्ति हेतु योगदान प्रदान किया जाना अभी भी शेष है;

यह सभा सरकार से शीघ्रातिशीघ्र निम्नलिखित कदम उठाने का आग्रह करती है-

(क) सर्वसमावेशी विकास के लिए व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण करे;

(ख) जल विद्युत, ताप विद्युत तथा कोयला-आधारित, तेल-आधारित, गैस-आधारित, सौर ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और परमाणु ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाए और "थोरियम" जो कि देश के अनेक हिस्सों जैसे केरल में उपलब्ध है, के विद्युत-उत्पादन में उपयोग के संबंध में अध्ययन कराए;

(ग) स्वीकृत वैश्विक मानकों के अनुसार विद्युत संयंत्रों को बन्द रखे जाने की अवधि को कम करे;

(घ) स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पारेषण में न्यूनतम हानि सुनिश्चित करे, और जवाबदेही तय करे;

(ङ.) उपभोक्ताओं द्वारा स्वप्रेरणा से अथवा कर्मचारियों के साथ मिलीभगत से बिजली की चोरी को क्रमिक रूप से रोके और अगले दस वर्षों में इसे "व्यावहारिक रूप से शून्य संवितरण हानि" के इसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाए;

(च) सेवा तथा सब्सिडी की लागत की वसूली करे;

(छ) अनुसंधान और विकास के माध्यम से प्रौद्योगिकी की शुरुआत करे;

(ज) उपभोक्ताओं के लाभ के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा की शुरुआत करे;

(झ) विद्युत-उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी या तथाकथित सरकारी-निजी साझेदारी के मार्ग को अपनाए;

(ञ) ऊर्जा-संरक्षण को मात्र संरक्षण सप्ताहों तक ही सीमित न रखा जाए बल्कि अधिमानतः 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ इनेर्जी एफिसिएन्सी' अथवा ऐसे किसी अन्य स्वतंत्र संगठन को तरजीह देते हुए उनके माध्यम से इसे ऊर्जा संरक्षण पद्धतियों का एक अभिन्न अंग बनाया जाए;

(ट) वर्तमान नियमों एवं विनियमों के अनुसार विहित पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन करे;

(ठ) गुणवत्ता आश्वासन के लिए मानव संसाधन के क्षेत्र में विशिष्ट रूप से निर्मित एवं गहन प्रशिक्षण प्रदान करे;

(ड) आगामी 100 दिनों में तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा, इत्यादि प्रत्येक राज्य में 4000 मेगावाट की कोयला-आधारित अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के माध्यम से क्षमता-संवर्धन करे और बिजली की भारी कमी का सामना कर रहे महाराष्ट्र जैसे राज्यों को इसी प्रकार के संयंत्रों के आबंटन के लिए भावी योजना बनाए;

(ढ) एनटीपीसी, डीवीसी, राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही समस्त विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समकालिक बनाए और ग्रामीण, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों सहित समस्त क्षेत्रों में विद्युत-आपूर्ति सुनिश्चित करे;

(ण) क्षमता संवर्धन लक्ष्यों, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपूर्ण रह गए थे, के संबंध में अध्ययन कराए तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्यों का मूल्यांकन करे और छमाही निगरानी के आधार पर वर्तमान विद्युत योजना की समीक्षा करने के बाद 12वीं तथा 13वीं योजना अवधियों के लिए भावी योजना तैयार करे; और

(त) विद्युत संयंत्रों की बाह्य सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ करे और राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा किसी भी संदिग्ध आंतरिक तोड़-फोड़ को बिल्कुल भी सहन न करे।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और इस सदन का भी मैं आभारी हूँ कि आज पूरा कोरम हो गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे सन् 1917 में रूस में हुई क्रांति का वह दिन याद आता है जब लेनिन ने जार को पराजित करके एक नव राष्ट्र का सूत्रपात किया था, लेकिन लेनिन ने उस अवसर पर अपने देशवासियों से कहा था कि हमें राष्ट्र निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होगी, एक तो प्रॉलिटेरियट का साथ तथा दूसरा निबार्थ ऊर्जा की आपूर्ति। ये दोनों चीजें राष्ट्र निर्माण के भाग्य का फैसला करेंगी। बाद की घटनाएं साबित करती हैं कि किस तरीके से uninterrupted power की बदौलत रूस ने विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया।

आज जो प्रस्ताव मैंने सभापटल पर बहस और सरकार के ध्यानाकर्षण के लिए रखा है, वह देश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के संबंध में है।

ऊर्जा हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की रीढ़ है। इससे हमारे जीवन के हर पहलू संचालित होते हैं। देश के ढांचागत विकास का यह महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए सरकार ने अपने पहले 100 दिन के कार्यक्रम में इसे स्थान दिया है तथा इस अवधि में 5,600 मेगावाट की वृद्धि निश्चित की गई है। Competitive rates पर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की जरूरत समस्त भारतीय उद्योग, जिसमें भारी माध्यम और लघु, कृषि, ग्रामोद्योग तथा घरेलू चीजों, के लिए है। अभी हाल ही में service sector में काफी प्रगति हुई है और outsourcing के लिए, ऑफिस वगैरह जो 24 घंटे चलते हैं, उनके लिए विद्युत एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बनी है। श्रीमती सोनिया गांधी जी, UPA Chairperson के नेतृत्व में कांग्रेस ने 2009 में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। श्रीमती सोनिया गांधी जी की यह आकांक्षा है - Power by 2020. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पंडित जवाहर लाल नेहरू ने विकासशील भारत की नींव रखी थी तथा इसके लिए उन्होंने औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक विकास, शैक्षणिक विकास और कृषि के क्षेत्र में विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियां बनाईं। इस समग्र विकास को प्राप्त करने के लिए विद्युत उत्पादन एक महत्वपूर्ण आयाम है। आजादी के बाद इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है लेकिन देश की बढ़ती हुई आबादी तथा सतत खुलते हुए विकास के रास्तों ने ऊर्जा की अधिक आवश्यकता की ओर पूरे देश का ध्यान परिलक्षित किया है। हमारे प्रधान मंत्री जी द्वारा न्यूक्लियर समझौता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में हमें ताप, जल और गैर पारम्परिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा। अभी हमारी आवश्यकता से कोसों कम विद्युत उत्पादन हो रहा है। इस संदर्भ में संसद ने वर्ष 2003 में Electricity Act पारित किया था, जिसके तहत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई। इस अधिनियम की धारा 3 में कहा गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, कोयले तथा प्राकृतिक गैस, न्यूक्लियर तत्वों अथवा सामग्री, जल तथा नदीकरणयुक्त ऊर्जा के अधिकतम उपयोग पर आधारित विद्युत तंत्र का विकास करने वाले प्राधिकरण से परामर्श कर समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत नीति तथा टैरिफ नीति तैयार करेगी। राष्ट्रीय विद्युत नीति के उद्देश्यों के तहत अगले 5 सालों में सभी घरों में विद्युत पहुंचाना ...(व्यवधान)... विद्युत की उपलब्धता तथा 2012 तक मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जाना, ऊर्जा की अधिकतम मांग के समय कमी को दूर किया जाना, ऊर्जा दक्षतापूर्ण ढंग से और उचित दरों पर निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता युक्त और विश्वसनीय विद्युत की आपूर्ति, 2012 तक प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता को 1,000 यूनिट तक बढ़ाना, 2012 तक मेरिट गुड के रूप में एक यूनिट प्रति घर, प्रतिदिन का न्यूनतम विद्युत उपयोग तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा शामिल है।

महोदय, इस नीति के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण, targeted subsidies तथा सेवाओं की लागत की वसूली, तकनीक विकास अनुसंधान, उपभोक्ता के लाभ के हेतु प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र की भागीदारी सहित विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रमों का वित्त पोषण, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरणीय मुद्दे, प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास सह उत्पादन और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत आदि भी तय किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत नीति से विद्युत संबंधी कोई भी मुद्दा अछूता नहीं रहा है, इसके लिए मैं ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन अगर इस नीति को हम वास्तविकता के धरातल पर देखें, तो पाएंगे कि लक्ष्य का निर्धारण करना आसान है और उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इस क्षेत्र में केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्र, तीनों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

महोदय, अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में दृष्टिपात करें, तो पाएंगे कि हम लक्ष्य से काफी पीछे हैं। वर्ष 2009 में विद्युत उत्पादन क्षमता 3,500 मेगावाट बढ़ी है, लेकिन क्षमता में बढ़ोतरी दयनीय है और यह 11,061 मेगावाट निर्धारित टारगेट से 68 प्रतिशत कम है। वर्ष 2010 में उत्पादन क्षमता में 4.6 प्रतिशत के साथ 7,730 मेगावाट

बढ़ोत्तरी की आशा है। वर्ष 2009-10 में कोलले और गैस की उपलब्धता को देखते हुए इस क्षमता में वृद्धि हो सकती है। इस समय देश की कुल विद्युत क्षमता 1,47,403 मेगावाट है, जिसमें से 93,393 मेगावाट ताप विद्युत है, nuclear power की क्षमता मात्र 4,120 मेगावाट है तथा जल विद्युत की क्षमता 36,648 मेगावाट है। विश्लेषकों का अनुमान है कि ताप विद्युत उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है, जब कि जल विद्युत में 8.4 प्रतिशत तथा nuclear power से मिलने वाली विद्युत में 12.3 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि 2009 में विद्युत उत्पादन में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लेकिन वर्ष 2008-09 में मांग और पूर्ति की औसत में 11 प्रतिशत की कमी आंकी गई है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 78,700 मेगावाट क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बारहवीं योजना के तहत एक लाख मेगावाट क्षमता की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। अगर लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को देखा जाए, तो दोनों में काफी अंतर दिखाई जाती है।

महोदय, दिनांक 10 जुलाई, 2009 यानी आज के ही एक समाचार पत्र में प्रधान मंत्री कार्यालय के एक नोट का जिक्र आया है, जिसमें विद्युत मंत्रालय के काम काज पर टिप्पणी है और इसमें कहा गया है कि कम विद्युत उत्पादन की वजह से देश की आर्थिक growth प्रभावित हो रही है। जहां चीन प्रति वर्ष एक लाख मेगावाट विद्युत क्षमता बढ़ा रहा है, वहीं भारत में यह बढ़ोत्तरी 3.454 प्रतिवर्ष है। भारत में जहां कुल स्थापित क्षमता 1,50,000 मेगावाट के लगभग है, वहीं चीन में 8,60,000 मेगावाट है। दिल्ली में ही पांच सौ मेगावाट की कमी महसूस की जा रही है। जहां तक मेरा अनुमान है कि देश के सभी क्षेत्रों में सिर्फ पॉवर सेक्टर ऐसा है, जो कि सभी क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है। इसके लिए हमें proactive सकारात्मक नीति की जरूरत है। हमने Electricity Bill के बाद Electricity Policy, Electricity Plan, Rural Electrification Policy, Tariff Policy आदि तमाम नियामक संस्थाएं बनाईं। Electricity Regulatory Authority, Power Grid Corporation, Power Finance Corporation इत्यादि अनेक rules और regulations तथा policies के बीहड़ में आंकड़ों से खेल करने लगे। जिसके कारण हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में दयनीय ढांचागत स्थितियां हमारे औद्योगिक विकास को धीमा कर रही हैं।

महोदय, इस विषय में 2012 तक 'Power for All' सिर्फ एक सपना बन कर रह जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि इस समय 11 प्रतिशत की कमी है तथा 2012 Plan Peaking Shortage 12.8 प्रतिशत है, ऐसे में 2012 प्लान को लक्ष्य में रखकर उत्पादन क्षमता में दो गुणा वृद्धि का लक्ष्य कहां तक साकार होगा। यह प्रश्न हमारे मन में है। पिछले तीन पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य तथा उत्पादन में पचास प्रतिशत का अंतर रहा है। ग्यारहवीं योजना यानी 2007-12 में 78,700 मेगावाट का लक्ष्य, दसवीं योजना के तहत हुए Capacity Addition से चार गुणा से भी ज्यादा है। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यह कैसे हो जाएगा? मंत्री जी इस सदन में इस बात की जानकारी देने की कृपा करेंगे।

महोदय, इस संबंध में एक और प्रश्न विचारणीय है कि हमारे 70 से 80 प्रतिशत कोयला पर आधारित Power Stations बीस साल से भी पुराने हो चुके हैं, जिनके नवीनीकरण के लिए काफी पैसे की आवश्यकता होगी। इस संबंध में जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की एक और कंपनी भेल की महत्वपूर्ण भूमिका है। पावर प्लांट्स को लगाने तथा दुरुस्त रखने के लिए हमारे सभी प्लांट्स को इस कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता है। BHEL तमाम मशीनों की आपूर्ति समय पर करने में असमर्थ रहा है। अभी Central Regulation Authority ने कहा है कि BHEL द्वारा समय पर मशीनों की आपूर्ति न कर पाने की वजह से तमाम projects को चालू करने में देरी हो रही है। BHEL देश की सबसे बड़ी कंपनी है। यह कंपनी इस समय प्रति वर्ष 10,000 मेगावाट की क्षमता की मशीनें बना रही है तथा अगले वर्ष इसकी क्षमता में 5,000 मेगावाट की वृद्धि की आशा है, जिसे मिलाकर वह 15,000 मेगावाट की हो जायेगी। अभी नए प्लान के तहत 2012 तक 78,577 मेगावाट उत्पादन बढ़ाया जाना है, जिसके ऑर्डर्स BHEL को दिए गए हैं। ऐसी

स्थिति में यह टारगेट कैसे हासिल होगा? पिछले पांच वर्षों में कुल लक्ष्य का कुल 49 प्रतिशत उत्पादन क्षमता हासिल करके 41,110 मेगावॉट का हमने addition किया है। साल 2007-08 में निर्धारित 12,000 मेगावॉट के लक्ष्य में सिर्फ 9,300 मेगावॉट का addition हुआ है। विश्लेषकों का अनुमान है कि 11वीं योजना में कुल लक्ष्य का सिर्फ 40 प्रतिशत से 45 प्रतिशत ही addition हो पाया है, इसके बारे में सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आप लगातार लक्ष्य बड़े अंतर से चूक रहे हैं, फिर दोबारा ऐसी नीति क्यों बनाते हैं, जो वास्तविकता से कोसों दूर है?

सर, अब एक नजर मैं जल-विद्युत उत्पादन पर डालना चाहता हूँ। Central Power Authority - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने देश में जल विद्युत की कुल 1,48,701 मेगावॉट की संभावित क्षमता का अनुमान लगाया था, जिसमें से स्थापित क्षमता 36,878 मेगावॉट है तथा 12,855 मेगावॉट के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। जल विद्युत की कुल विद्युत उत्पादन से हिस्सेदारी 24.92 प्रतिशत है। अगर हम पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक की योजनाओं पर नजर डालते हैं, तो पाएंगे कि जल विद्युत की हिस्सेदारी कुल उत्पादन में लगातार कम होती गई है। पहली योजना में 63 प्रतिशत, दूसरी में 41 प्रतिशत, तीसरी में 45 प्रतिशत, चौथी में 41 प्रतिशत, पांचवीं में 40 प्रतिशत, छठी में 34 प्रतिशत, सातवीं में 82 प्रतिशत, चौथी में 41 प्रतिशत, नवीं में 25.40 प्रतिशत और दसवीं में 26 प्रतिशत - ऐसा क्यों हो रहा है? इस संबंध में National Hydro Power Corporation ने कुछ कारण बताए हैं। इनमें कठिन और दुर्गम स्थल, भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याएं, कानून और व्यवस्था की समस्या, धन की कमी, लंबी पूर्णता अवधि, भौगोलिक भूगर्भिक समस्याएं, अंतर्राज्यीय विवाद तथा विभिन्न लाभ भोक्ताओं के बीच परियोजना लागत के विभाजन पर सहमति का न होना आदि। इसी के साथ पर्यावरण के संबंध में मंजूरी में देरी, वन क्षेत्र समस्या, स्थानीय निवासियों, ग्राम पंचायतों आदि के द्वारा एन.ओ.सी. में बाधा, downstream क्षेत्रों की समस्याएं आदि - इन सभी समस्याओं की वजह से काफी परियोजनाएं या तो लंबित पड़ी हैं या उन पर काम बीच में रुका है। केन्द्र सरकार को इन विषयों पर, विशेष रूप से पुनर्वास और विस्थापन जैसे मुद्दों पर परियोजना शुरू करने से पहले विचार करना चाहिए तथा सारी समस्याएं सुलझाने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। एनएचपीसी के संबंध में एक बात प्रकाश में आई है कि वहां पर कर्मचारियों और इंजीनियरों का पलायन हो रहा है। वैसे ही यह क्षेत्र ठेकेदारों की समस्या से जूझ रहा था। पता चला है कि गत वर्षों में 500 के लगभग कर्मचारी एनएचपीसी छोड़कर निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में चले गए हैं और अब एनएचपीसी इस समस्या से निपटने के लिए बाहर से लोगों को contract पर ले रही है। इस समय एनएचपीसी 12 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है तथा 2012 तक इसने 16,500 मेगावाट ऐडिशन का लक्ष्य रखा हुआ है। सरकार बताए कि यह लक्ष्य इन सारी समस्याओं को सामने देखते हुए कैसे पूरा होगा? गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए नीति में राष्ट्रीय गैस ग्रिड स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। अब तक इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या निजी क्षेत्र को भी इस ग्रिड से आपूर्ति संभव है? क्या विद्युत उत्पादक विद्युत संयंत्रों के लिए गैस और कोयले की आपूर्ति के लिए लम्बे टेंडर भर सकते हैं? यदि ऐसा है तो क्या इसके लिए कोई आदर्श करारनामा आपने तैयार किया है? ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं? क्योंकि केन्द्र ने सबको बिजली मुहैया कराने की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के कार्यान्वयन हेतु आरईसी, राज्य सरकारों और राज्य डिस्कॉम के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की स्थिति बहुत ही दयनीय है। 56 प्रतिशत के लगभग ग्रामीण घरों को अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है जबकि ग्रामीण विद्युतीकरण की नीति के तहत आरजीजीवीवाई नेटवर्क में प्रतिदिन न्यूनतम 6 से 8 घंटों की बिजली आपूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी, जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत तथा अपेक्षित सब्सिडीकृत शुल्क पर बिजली आपूर्ति

3.00 P.M.

कर इस परिप्रेक्ष्य में होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय घाटे की पूर्ति का आश्वासन शामिल है। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु संसाधन हिस्सेदारी के संबंध में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण संरचना सृजन हेतु 90 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी देगी और 11वीं योजना में स्वीकृत आरजीजीवीवाई परियोजनाओं के लिए गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 2200 रुपए देगी, शेष 10 प्रतिशत सब्सिडी राज्यों द्वारा अपने संसाधनों, वित्तीय संस्थाओं से ऋण के जरिए दी जाएगी। इतनी महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता है जिससे ईमानदारी के साथ इसका निर्वाह किया जा सके। लेकिन तमाम प्रदेशों में अभी भी ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं पहुंच पाई है। तमाम गांवों में विद्युतीकरण का काम किया गया है। कुछ दिन वहां पर बिजली भी आई लेकिन अब सिर्फ खम्बे बचे हैं जो कि गाय और भैंसों बांधने के काम आते हैं और गांव वालों के पशुओं के लिए खूंटों का काम कर रहे हैं। वहां पर बिजली नहीं है फिर भी लोगों को शुल्क भरना पड़ रहा है। इसी प्रकार प्रदेशों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में काफी भ्रष्टाचार है।

इसलिए इसके लिए निगरानी तंत्र मजबूत होना चाहिए। केन्द्र सरकार की योजना है। इसके लिए मॉनिटरिंग के साथ ही दण्ड का भी प्रावधान होना चाहिए। जुलाई, 2007 में केन्द्रीय विद्युतीय प्राधिकरण ने एक सम्मेलन कराया था, जिसमें उत्पादन, ट्रांसमिशन से जुड़े कुछ मुद्दों को उठाया गया था। ये मुद्दे क्या हैं तथा इस पर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? जहां तक मुझे पता है, इन मुद्दों में एमैन प्लांट मशीनरी की उपलब्धता थी। अभी भेल के अलावा मशीनरी की आपूर्ति कौन कर रहा है, कितनी आपूर्ति बाकी है, कितने आर्डर्स प्लेस किए जा चुके हैं? मेरी जानकारी के मुताबिक कुल मशीनरी का 20 प्रतिशत का आर्डर अभी भी जाना बाकी है। इसे कौन मॉनिटर कर रहा है और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत मशीनरी आपूर्ति की स्थिति क्या है, कंस्ट्रक्शन मशीनरी की कमी के संबंध में भी बात सामने आई है, फोर्जिंग और कास्टिंग मेटिरियल के बारे में क्या स्थिति है, सिविल ठेकेदारों के बारे में क्या एजेंसी की कमी है तथा इसके बारे में क्या हुआ है, प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है, काफी प्रोजेक्ट्स कई वर्षों से लम्बित हैं, जिसकी कॉस्ट बढ़ रही है।

कोयले की कमी के बारे में क्या किया गया, इस समय कितना कोयला आयात किया जा रहा है, कोयले के अधिक उपयोग से वातावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर कोई विचार हुआ है? अभी 20440 मेगावाट क्षमता वाले गैस प्लांट्स के लिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूरे होने हैं, उसके लिए 66.61 एम.एम.एस. सी.एम.डी. गैस चाहिए, जबकि उपलब्धता सिर्फ 37.45 एम.एम.एस. सी.एम.डी. है। जहां तक कोयले की मांग और आपूर्ति का सवाल है, आज के समाचार पत्र की खबर के मुताबिक एन.टी.पी.सी. के पास कोयले के स्टॉक की स्थिति बहुत ही खराब है। एन.टी.पी.सी. के पास 15 पॉवर स्टेशनों में से पांच के पास इस समय बहुत ही कम स्टॉक है तथा तीन सुपर क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच चुके हैं, चार दिन का स्टॉक सुपर क्रिटिकल माना जाता है। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्लांट अपनी आवश्यकता का सिर्फ 50 प्रतिशत कोयला ही प्राप्त कर पा रहे हैं। देश के 78 थर्मल पॉवर स्टेशनों में से 11 के पास स्टॉक सुपर क्रिटिकल स्टेज में है। ऐसी स्थिति में सरकार क्या कदम उठाने जा रहा है?

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के लिए 5,60,000 अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी। इस क्षेत्र में प्रशिक्षित और स्किल्ड लोगों की पहले से कमी है तथा तमाम लोग हमारे पी.एस.यूज. छोड़कर निजी संस्थानों में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे लक्ष्य का क्या होगा? प्रशिक्षण के क्षेत्र में हमारे पी.एस.यूज. ने क्या किया है? ट्रांसमिशन के क्षेत्र में मिनिमम नुकसान की बात पॉलिसी में कही गई है। अभी देश में 33 प्रतिशत से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय विद्युत नीति में व्यक्त नीतियां क्या हैं तथा हम उन्हें कहां तक प्राप्त कर पाए हैं? केप्टिव विद्युत संयंत्रों से राष्ट्रीय विद्युत योजना में योगदान के किस स्तर की संकल्पना की गई है और राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड में इसके योगदान का स्तर क्या है, केप्टिव विद्युत उत्पादन के सामने आने वाली कौन सी बाधाएं हैं, विशेष रूप से ट्रांसमिशन के क्षेत्र में निजी भागीदारी की स्थिति क्या है? तथा इस समय राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसमिशन की वस्तु संरचना क्या है? राज्य विद्युत बोर्डों के पुनर्गठन की स्थिति क्या है? क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस बारे में बात की है? अक्सर ग्रिड से ज्यादा पावर लेने के बारे में सुनने में आता है? क्या इस बाबत आपने रूल्स तैयार किए हैं? क्या आपने किन्हीं राज्यों को ज्यादा पावर लेने की स्थिति में फाइन किया है? अगर हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव का उद्देश्य बहस करके सरकार का ध्यान विद्युत की गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करने का है। अब स्थिति यह हो गई है कि दिल्ली जैसे शहर में भी लोग जेनरेटर और इन्वर्टर का सहारा ले रहे हैं, तो गांवों की स्थिति क्या होगी? मुझे अंत में दुष्यंत कुमार की कविता की चंद पंक्तियां याद आ रही हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे कवि मन के मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे-

कहां तो तय था चरागां हर एक घर के लिए,

कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Thank you, your honour, for having given me this opportunity to take part in this very important discussion. I congratulate Shri Vijay Jawaharlal Darda for bringing up such an important resolution for consideration, discussion and debate by this august House. In fact, he has so beautifully presented his case that, I feel, it could be a subject matter of a thesis for PhD. He has been thought-provoking as well as thought-boggling. He has said so much and has raised so many questions that, I think, the hon. Minister of Power must be fully busy with the questions raised by him. I would only mention that as far as the human progress is concerned, there is hardly any debate on this that some sort of source of power or energy is required. In our country, this is also not debatable that there is a shortage of power and energy, and it has become a chronic shortage, which is a matter of concern. If you permit to trace a kind of history of civilizational progress, we would recollect that the first step was - in the stone age, by chance, a spark was found and element of fire was discovered-when pre-historic man found out, by chance, that friction of two pieces of stone produces a spark. That was virtually a spark of life. The first invention that the civilization had was fire. Another invention, if we go through that, was wheel. The third invention, we can say, was steam. The fourth invention is electricity. Electricity is virtually another name for *agni*,

which is one of the five elements, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा – earth, water, fire, sky and air. So, fire is one of the very important elements and electricity gives us warmth, heat as well as light. In fact, we invoked *agni* in our Vedas “तमसे मा ज्योतिर्गमय take us from darkness to light” and that is what we expect from our hon. Power Minister. Your honour, you will be delighted to know and I think you know it already that first *sloka* of Rigveda is अग्नि इले पुरोहितम् It starts with an invocation to *agni*. So at present, *agni devta* is our Power Minister and we expect from him all kinds of help in taking the country ahead. As far as India is concerned, India is the Sixth largest consumer of energy accounting for 3.4 per cent of global energy consumption. The installed capacity as on March, 2009, was 1,47,000 MW. In 1986, generation of electric power was 190 billion KWH which increased to 860 KWH by 2006. It is surprising to see what kind of a progress we have made. Initially, our generation capacity was merely 1,300 megawatt at the commencement of Independence and at the commencement of the Tenth Five Year Plan, it rose from 1300 megawatt to 1,00,000 megawatt. Progress has been significant but demand is so much, the need is so much that more power is required and that is the problem and that is the crux of the issue also. What ails Indian power sector, what the power sector scenario is and how we can improve things; that should be the focus of our discussion. As far as per capita consumption is concerned, it is very much below in India as compared to I think, the Minister of Power is busy in deliberations. I will stop for a while. Is it all right, Sir?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): My one ear is to you and the other ear is to him.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: But I want both the ears to me. One won't do.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Okay.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Very kind of you, Sir. I am a handicapped person; so, I need both the ears.

I will, again, submit your honour that per capita consumption in India is only 612 KWH which is very much below as compared to developed countries. If it becomes equal to developed countries, we will be in a morass, we will be in a great trouble because we won't be able to produce electricity to that effect. As far as composition of India's installed power capacity is concerned, Shri Vijay Jawaharlal Darda has already explained in detail starting from the First Plan to the Tenth Plan and the Eleventh Plan, but I will submit by saying what the situation at present is. Thermal is 64.6 per cent. Thermal is the largest sector as far as electricity production is concerned. Hydel is 24.7 per cent. It has been coming down. Hydel is the cheapest, but somehow because of many constraints which the hon. Minister knows better and, perhaps, they can be to some extent controlled also, it has come down to 24.7 per cent. Nuclear is just starting, it is at an infancy stage, that is, 2.9 per cent.

Renewable is 7.7 per cent. We have ignored the Sun God very badly. Sun is an unlimited source of energy, unlimited source of power, unlimited source of fire, the luminous planet in the sky, but we have not been able to make use of that.

In Rajasthan, we have Jodhpur, an important town your honour, which is known as *Suryanagari*, Sun City because during the year largest sun shine throughout the country is on that city. But there is hardly any installation of creating energy by Sun power. Similarly, *Vayu Devta* is there; wind energy is also very much less. Electricity production by air or by wind is also very much little. All our coastal area is there where winds are like anything; it can be generated. As far as waves are concerned, *Jal Devta*, I think, we have not been able to take much advantage of that also. Coal, we have been eating up, believing that it is unlimited reserve, which is a myth. We have the reserves, but it can't be unlimited; it will be never unlimited. Sun energy is, in one way, unlimited. Air energy is another way unlimited; water energy, is also unlimited, provided we are able to take advantage of that. As far as coal is concerned, India has world's third largest coal reserve. Hence, maximum energy is thermal energy.

Lignite is another factor which has not been taken proper care of, which should be exploited. Government's commitment to provide power for all by 2012, it is worth adoration that such a target has been set. But will it be possible to achieve? That is the main thing. The present scenario of electricity power in India—State sector, 52.5; Central sector, 34; private sector, 13.5. I mean, that is the percentage of overall energy bids by State, Centre and private sector. When we look into it, private sector has only 13.5 per cent share of energy production. My submission is to the hon. Power Minister that this source can be tapped further. By public participation, private sector participation, I think, more energy can be developed. There can be regulations which can force them to have captive power houses in their factories, in their installations. Central sector also needs to do more and it will be possible if we are able to fulfil our dream of nuclear energy. I would not like to rub what has been published in today's *Hindustan Times* because, I think, that is unkind to our hon. Power Minister, Shri Sushilkumar Shinde, and his name doesn't permit me to be critical as far as my remarks are concerned. He has been a very generous and good person. This has been referred by Mr. Darda also, 'PMO note slams Power Ministry.' I mean, it is not in good taste to say that. But, unfortunately, the note says, "a symptom of the deep malaise in the power sector." "Persistent shortfalls on account of electricity generation, held back our GDP." It is said, Delhi is facing such and such shortage and those details are given. This is a note by a very responsible person, T.K.A. Nair, Principal Secretary to the PMO's Office. "Having conspicuously failed to add even 50 per cent of the target capacity of 44000 MW in the Tenth Plan, the leaders of this sector pitched for an absolutely high target of 78,000 MW in the 11th."

With your Permission, Sir, I shall quote from the latest Economic Survey. It has also highlighted the deceleration in GDP growth and has pointed out, "The electricity sector continues to be

hampered by capacity constraints. The growth in electricity generation by power utilities during 2008-09 at 2.7 per cent fell much short of the targeted 9.1 per cent". We targeted 9.1 per cent and we fell to the ground by achieving only 2.7 per cent! This is what has been said in the Economic Survey. Something needs to be done here, Sir. As far as the earlier performance is concerned, I would like to quote: "Electricity generation in 2003-04 at 558.1 billion kwh was 4.5 per cent above the generation in the same period of the previous year." There was progress earlier, up to 2004, but now there is deceleration. I do not intend to point out any partisan figure but it needs consideration. It needs examination. It needs remedial measures. What are the constraints that have been mentioned? With your permission, Sir, I shall just spell them out. Lower capacity utilisation is one constraint. There are figures showing how much per cent less capacity utilisation has been done. Secondly, there are very high transmission and distribution losses. At the Central level, it is much better in the case of power projects. At the State level, it is something quite alarming in the case of electricity boards. Thirdly, there are huge operational losses perennially being incurred by State Electricity Boards. There are details shown about how much the losses are. The annual losses of SEBs at the end of the Ninth Plan were estimated at Rs. 24,000 crores, which led to large outstanding dues to Central public sector undertakings amounting to Rs. 35,000 crores. It is thousands and thousands of crores of losses which we are incurring.

One point, which has been rightly pointed out by the mover of this Resolution is, rampant corruption in the State Electricity Boards and even in Central organisations. A villager can get no connection without paying something. Even in the city, a man has to pay for getting a connection. There are cases of meters not working and linemen exploiting. It has virtually become a cesspool of corruption. With a man of the Power Minister's integrity at the helm of affairs, I hope, something will be done to stem the rot. As far as the pitiable condition of the villagers is concerned, I think it might sound exaggerating, but as Mr. Darda very rightly pointed out, poles without electricity running in the wires are used for tying cattle. वे खूँटे का काम करते हैं। पोलस खड़े हैं, लेकिन बिजली नहीं है। गांव के अंधेरे में भी प्रकाश पहुँचे, that is what should happen. At present, 56 per cent villages are virtually without electricity. Statistics might be saying anything; even if there is one bulb in a village, you say the village is electrified; in fact, it is a travesty. You must go to the villages and see the condition for yourself. You will get to know what the person there feels. As far as the first charge on electricity is concerned, it is that of the farmer and that too, of the poorest farmer. In cities we have enough of चकाचौंध। They have a new 'sun' everywhere, but as far as villages are concerned, they are still worse off and that should be the first task as far as the farmer is concerned. For him electricity is his lifeline. Without that he cannot draw groundwater; without that his tube well is not working and without that his crop withers. So, how much share should be of a farmer and which kind of priority should be given to a farmer, that must be looked up. Farmer is not able to put forward his plight or his plea or his claim. It is for you to look up. Industry naturally needs power. The first charge is of agriculture because 65 per

cent of population lives on agriculture. Agriculture is the backbone of the nation and agriculturist must get electricity eight hours a day minimum continuously. But he does not get, at times, even one hour of electricity in a day. That is what is happening. I will again repeat or re-emphasise that it should also be considered which kind of environmental pollution is resulting because of our power-houses and different kind of our schemes. In that context, nuclear power will be the real and right one; solar power will be the right one; wind energy will be the right one and tidal energy will be the right one because there will be least pollution or no pollution at all. Thermal power is giving biggest pollution in the form of fly ash. That has to be looked up. One point which has not come up so far is theft of power. Both corruption and theft eat into the revenues. As far as distribution and transmission losses are concerned, they are in the system. By that individual does not get advantage. But by corruption and theft individual gets advantage. Let it be checked. I think, Sir, I have talked enough and there is enough for you to do. I have all hope and expectation that a man of your eminence and calibre will be able to get over all difficulties in the way of progress. Ignoring whatever PMO has written, I am sure you will be able to come out with fresh figures and best of niche in the history of Power Ministers in this country. Thank you.

श्री गंगा चरण (उत्तर प्रदेश) : महोदय, सबसे पहले मैं श्री विजय कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्होंने जो रेजोल्यूशन पेश किया है, इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं। आज सारा देश बिजली के संकट से जूझ रहा है और इन्होंने मंत्री जी का एवं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, आज बिजली संकट पूरे देश की समस्या है, जन-जन की समस्या है। लेकिन जिस तरह सरकार को इस संबंध में गंभीर होना चाहिए, उस तरह सरकार और बिजली मंत्री गंभीर नहीं हैं।

श्री उपसभापति : पीठासीन हुए।

पिछले वर्ष न्यूक्लियर डील हुई। उस न्यूक्लियर डील के आधार पर ही सरकार को जनादेश मिला और पुनः कांग्रेस की, यूपीए की सरकार बनी। लेकिन न्यूक्लियर डील पर जिस तरह की प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, उस तरह की प्रोग्रेस देश की जनता को दिखाई नहीं दे रही है। हमारे दो साथियों ने न्यूक्लियर पावर के अलावा भी कुछ और विकल्प रखे हैं, उन विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार होना चाहिए।

आज पूरे देश में और राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में भी बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। वी.आई.पी. इलाकों में भी बिजली की कटौती हो रही है। बिजली की वजह से पानी के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। इस बात को सरकार को एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए।

विद्युत उत्पादन के लिए और भी कई विकल्प रखे गए हैं। मेरा सुझाव है कि हर डिस्ट्रिक्ट को कितनी बिजली की आवश्यकता है, उससे कम-से-कम 50 परसेंट बिजली का उत्पादन उसी जिले में होना चाहिए जो अन्य विकल्प दिए गए हैं, उनसे, चाहे वह और सौर ऊर्जा का उत्पादन हो या जैसे आजकल कचरे से भी बिजली बनने लगी है।

इसलिए जिले में जो कचरा निकलता है, उसका भी सदुपयोग हो और उससे भी ऊर्जा का उत्पादन होना चाहिए। कचरे से पैदा होने वाली बिजली की जो टेक्नोलॉजी है - चाहे वह देशी टेक्नोलॉजी हो या विदेशी टेक्नोलॉजी हो - उस टेक्नोलॉजी का एडॉप्ट करके सरकार को हर जिले में कचरे से विद्युत का उत्पादन सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा विकल्प पनबिजली का है, पानी से विद्युत के उत्पादन। बरसात के समय हम पानी से भी बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। हम सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं तथा हवा के द्वारा भी बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन इन विषयों पर सरकार ने अभी तक गम्भीरता से कोई काम नहीं किया है। सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट पर एक समय सरकार ने 50 परसेंट और कहीं-कहीं 70 परसेंट भी अनुदान दिया है। खास तौर से ग्रामीण अंचलों में इसके लिए सरकार को ग्रामीण सभाओं को अनुदान देना चाहिए कि वे ग्राम सभाएं ही गांवों में सौर ऊर्जा का उत्पादन करें। गांव में जितनी बिजली की आवश्यकता हो, उसके लिए सौर ऊर्जा के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स उन गांवों में लगाए जाएं। इसका कारण यह है कि जब हम शहरों को ही बिजली नहीं दे पा रहे हैं, और इंडस्ट्रीज को ही बिजली नहीं दे पा रहे हैं तब में तो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हूँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ इसलिए मुझे यह पता है कि गांवों में हफ्तों तक बिजली नहीं आती है और उसके अभी आने की उम्मीद भी नहीं है। इसलिए गांवों को सौर ऊर्जा से बिजली की आपूर्ति की व्यवस्था हो, ऐसा प्रबंध सरकार को करना चाहिए।

इसी तरह हवा से भी बिजली का उत्पादन गांवों में किया जा सकता है। जल-विद्युत का भी उत्पादन गांवों में किया जा सकता है। इसके साथ ही गांव में किसान का जो भूसा होता है या कचरा होता है, उससे भी विद्युत का उत्पादन गांवों में किया जा सकता है। ये सारे प्रोजेक्ट्स सरकार को जिला स्तर से लेकर गांव स्तर तक लगाने चाहिए, जिससे कि बिजली की जो मांग है, उन्हें इन छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स के द्वारा पूरा किया जा सके। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तथा बड़े शहरों के लिए न्यूक्लियर पावर से या कोयले से जो बिजली का उत्पादन होता है, उनसे आपूर्ति कर सकते हैं। इस विषय में केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों, राज्यों के जो ऊर्जा मंत्री हैं, उनके साथ बैठ कर वार्ता करनी चाहिए तथा जिस राज्य में जितनी जरूरत है, उस राज्य को उसकी आबादी के अनुसार बिजली देनी चाहिए।

आज विद्युत वितरण का काम एन.टी.पी.सी. करती है। लेकिन, आज उसमें भी पोलिटिक्स होने लगी है। किस राज्य में कांग्रेस की सरकार है, किस राज्य में यू.पी.ए. के घटक दल की सरकार है, उसे ज्यादा बिजली देंगे, लेकिन जहां विरोधियों की सरकार है, वहां उससे कम बिजली देंगे। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहां पर क्योंकि बी.एस.पी. की सरकार है, इसलिए केन्द्र सरकार से, एन.टी.पी.सी. से, उसको बिजली नहीं दी जा रही है। वहां हाहाकार मचा हुआ है। महोदय, एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन चलाती है और दूसरी तरफ बिजली भी नहीं देती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का अन्यायपूर्ण व्यवहार केन्द्र सरकार को नहीं करना चाहिए। महोदय, अगर वहां जनता ने बी.एस.पी. की सरकार बनायी है तो उसने कोई कसूर तो नहीं किया है, फिर इसकी सजा आप जनता को क्यों दे रहे हैं? उसकी सजा जनता को नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार केन्द्र सरकार को बदलना चाहिए और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। यही मेरा सुझाव है। धन्यवाद।

श्री राजनीति प्रसाद : धन्यवाद, महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज देश को आजाद हुए करीब 60 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी देश में जैसा बिजली का infrastructure बनना

चाहिए, लोगों को बिजली मिलनी चाहिए, उस मुताबिक उन्हें बिजली नहीं मिल पाती है। आखिर इस का कारण क्या है? महोदय, इस बारे में अभी तक बहुत शोध नहीं किया गया है। अगर इस पर शोध किया जाता, तो संभव है कि जिस तरह से अन्य देशों, जैसे चीन और दूसरे देशों में बिजली का अभाव नहीं रहता हमारे यहां भी बिजली का अभाव नहीं रहता।

महोदय, पिछले 20 वर्षों के अंदर सौर ऊर्जा पर बहुत कारगर रिसर्च हुई है। पहले गांवों में सौर ऊर्जा से टिवरी जला करती थी। उसकी एक तकनीक है। अभी हम लोग बाहर गए थे तो देखा कि हमने सौर ऊर्जा के कुछ प्रोजेक्ट्स बाहर के लोगों को दिए हैं। लेकिन अभी भी सौर ऊर्जा के बारे में बहुत रिसर्च नहीं हुई है। अगर इस बारे में बहुत रिसर्च होती तो कुछ गांवों में जहां बिजली नहीं रहती है, वहां हम बिजली पहुंचा सकते थे। महोदय, कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां अगर बिजली आ गयी तो मानो कोई त्योहार हो गया। वहां लोग सोचकर चलते हैं कि बिजली नहीं रहेगी, लेकिन जब वहां बिजली आती है तो लगता है जैसे कोई त्योहार हो गया। लोगों के चेहरों पर चमक आ जाती है, लेकिन वहां बिजली सिर्फ घंटे-दो घंटे के लिए रहती है और वह भी कब आती है, कब जाती है, यह लोगों के लिए एक खास विषय बना रहता है। बिजली कब आएगी और कब जाएगी, इस का कोई नियम नहीं होता है।

महोदय, आज से कुछ महीने पहले सरकार बिजली के संबंध में एक प्रस्ताव लाई थी कि हम बाहर से बिजली लेंगे। उस पर हमारे कुछ साधियों ने समर्थन भी वापस लिया था। मैं पूछना चाहता हूं कि बिजली के बारे में उस समय जो बात हुई थी, उसका क्या हुआ? उस बारे में क्या काम किया गया, उस पर क्या कार्रवाई हुई और उस पर क्या प्रगति हुई, यह हम लोग जानना चाहेंगे?

महोदय, पन-बिजली अभी संभव नहीं है क्योंकि सब जगह बरसात नहीं होती है। हमारे यहां नदियों को बांधा नहीं गया है। अगर नदियों को बांधकर धारा बनाते तो हो सकता था पन-बिजली हम को मिलती। यह थर्मल पावर का प्रोजेक्ट भी हमारे यहां लैप्स कर दिया है क्योंकि वहां ठीक से कोयला नहीं मिलता है और जब कोयले की supply नहीं मिलेगी तो बिजली कैसे तैयार होगी? यह भी कहा गया कि थर्मल को भी बिजली चाहिए।

महोदय, मैं एक बात हमेशा कहना चाहता हूं। कहीं ऐसी जगह बिजली का उत्पादन होता है। एक उदाहरण के लिए मैं कहलगांव का नाम लेता हूं। कहलगांव में जब बिजली उत्पादन की जा रही थी तो वहां के लोगों ने कहा कि यहां से अगर बिजली जाएगी तो इसमें हमारा भी कोटा मिलना चाहिए। सर, कहलगांव भागलपुर के पास है। इसके लिए वहां लड़ाई-झगड़ा हुआ और पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। बिजली जिस जगह पैदा होती है, उस जगह पर इसलिए झगड़ा हो गया कि हमारे इलाके में आप बिजली पैदा कर रहे हैं तो आप बिजली का शेयर हमको भी दीजिए।

सर, आजकल बहुत गरमी पड़ती है। मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां बहुत गरमी पड़ती है। अभी तो यहां भी बहुत ज्यादा गरमी है, लेकिन आप लोगों ने सुविधा दी है। जहां भी बिजली दो-दो घंटे के लिए चली जाती है। अभी पार्लियामेंट में भी एकाध दिन बिजली चली गई थी। अब पता नहीं उसमें कमी-बेशी हो गई है। सर, जो घर एयरकंडीशन होते हैं। वहां जब बिजली चली जाती है तो किसी जनरेटर से भी एयरकंडिशन नहीं चलता। आदमी पूरे मकान को घेर कर रखता है। खिड़की बंद करके रखता है। उसमें कपड़े और कूट लगाता है। जब मकान बंद हो जाता है और बिजली चली जाती है तो गरमी बहुत ज्यादा महसूस होने लगती है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना

चाहूंगा कि इसके लिए आप कोई उपाय निकालिये। हमारी आबादी भी बढ़ रही है और लोगों के उपभोग के नये-नये साधन भी बढ़ रहे हैं। हमारे यहां फैक्टरियां भी बढ़ रही हैं। हमारे यहां रहन-सहन का स्तर भी बढ़ रहा है। इसलिए अगर आप बिजली के बारे में कोई नया अनुसंधान नहीं करेंगे तो हमारे यहां बिजलियां नहीं मिलेंगी।

सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मरने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। अगर आदमी मर गया तो उसके लिए भी बिजली की जरूरत होती है। गरीब लोग पार्थिव शरीर को लकड़ी से नहीं जला सकते हैं, वह बहुत महंगी होती है, वहां 160 रुपये मिलती हैं। वहां बिजली नहीं रहती है। आपने शवदाह गृह तो बना दिया, लेकिन वहां बिजली ही नहीं है। अगर वहां बिजली नहीं है तो वह चलेगा ही नहीं। इसलिए गरीबों के लिए भी बिजली की जरूरत है। आप बिहार के शहरों और देहातों में जाइये। वहां आठ-आठ और दस-दस दिनों तक बिजली नहीं आती है। वहां और क्या होता है? वहां पर्यावरण का भी सवाल होता है। पर्यावरण क्या? वहां हर शहर, गांव, टोला और बाजार में जेनेरेटर चलता रहता है। उससे इतना धुआं होता है कि वहां से आदमी pass नहीं कर पाता।

सर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली के उत्पादन के लिए कोई नई खोज - जब आप चांद पर जा रहे हैं, जब आपका इलैक्ट्रॉनिक सामान इतना बढ़ गया है तो नई खोज, नई चीज निकालने की जरूरत है। अगर आप नई चीज नहीं निकालेंगे तो फिर हम लोगों की उम्र तो जितनी हो गई सो हो गई, हमारे बच्चे भी कहेंगे कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बिजली अभी भी टिमटिमाती है। अभी भी बिजली नहीं रहती है और अगर एक मोहल्ले में दो-तीन जेनेरेटर चलने लगे तो उनसे इतनी आवाज होती है कि रात भर कोई सो नहीं पाता है।

सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि एटॉमिक एनर्जी पर जो समझौता हुआ था, उसके बारे में आपने क्या किया? कहां से सामान आया? कौन-सा सामान आया? उसमें आपने कहा था कि हम बिजली का - कलावती वगैरह का नाम लिया गया था जो डिबरी में पढ़ती थी, उसका नाम लिया गया। इतने दिन बीत गये - मेरे ख्याल से सात-आठ-नौ महीने बीत रहे हैं। उसके बारे में आपने क्या काम किया?

सर, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ और वह यह कि उन्होंने भी दुष्यंत की कविता से खत्म किया था और मैं भी उसी से खत्म कर रहा हूँ,

"बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,

इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए,

मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में हो,

हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, बिजली जलनी चाहिए।"

धन्यवाद सर।

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, first of all, I congratulate my friend Shri Vtjay Darda and support the Resolution moved by him. It is a very important matter which catches the attention of the entire Indian people. Now, the hon. Minister for Power is working very hard to reach the targets which he has already fixed as power for all by 2012 to the level of two lakh megawatt. At the same time, we have already installed capacity of 1,50,000 megawatt. Sir, we have to compare ourselves with the other big brothers who are sitting nearby, that is, China. They have got target of 8,60,000 megawatt. Their capacity now is one lakh megawatt per year. But, our

capacity is only 3,454 megawatt. Sir, even now we are going very conventionally and we are depending only on the thermal power and also on the other fossil fuel. Other than that, the nature has given us a lot of energy through solar and wind power. These two areas have never got so much of attention. We put it as one of the non-conventional energy sources. Even a small tool or a solar panel will cost too much. A small bulb will cost Rs.200 or Rs.300. Therefore, people do not at all have a feeling that we can utilise the solar power which nature has given us.

Sir, I just want to draw the attention of the Government that we have to involve the people also for power generation. It is not that people need to procreate their children alone. Even a simple man in the remote village can generate power by utilising the solar energy. Sir, I have the direct knowledge of going to Germany and seeing the people there. There the Government allows individuals to put solar panels on top of their houses. Their system is like this. The energy which is produced from that panel is separately monitored and measured. For that, they will pay six times more than what is the actual market rate per unit. At the same time, whatever power comes out of their house is connected to the national grid. That national grid will measure. From the national grid, they can take electricity for their own usage. That will also be subsidised. Therefore, in Germany, where only 30 per cent of the solar energy is available, they are making the people participate in generating electricity. But, here, we have got 103 crore people who are anxious to have electricity. Even small houses want to have it. This time the UPA Government has made a Budgetary provision of Rs.7,000 crores just to provide lights to the ordinary poor people. If we make a provision of Rs.7,000 crores for giving solar panel to every house in a remote village, we can save the energy which is now lost in transmission. More than 40 to 45 per cent transmission loss is there. Therefore, we can save that energy and utilise it in the cities. In remote areas, they have a pattern of having a gap of around 20-25 kilometres between one village and another. Even for the purpose of electronic communication usage, we are putting a cable unnecessarily. We can have dish antennas everywhere so that we can save the money. Similarly, for this solar photovoltaic system, we can very easily involve the people. There are more than 50 crore households. Even a small man in cottage can generate electricity for their own use and provide it to the national grid also. Therefore, we have to think in a different way and I feel that it should not be treated as non-conventional. I feel, it should be a part of the Power Ministry, and they have to concentrate too much on it, and if it is taken as a national project, then naturally, when we are making a unit worth Rs. 50 crores, the cost will be very much reduced, and minimum cost will be there, and millions of unemployed youths will get jobs. We can take the example of Ladakh in our own country. Ladakh is fully supported by the solar energy. Every house is having the full capacity of electricity even though the conventional energy is coming. But at the same time, they are utilizing the solar energy for the purpose of heating water and also for the purpose of using it in the household. In the deserts of Rajasthan, people have now started using the solar power for pumping water, half horse power or one horse power. This type of change of mind has to come to

our planning system. The Planning Commission should also think on those lines. We need not borrow the same ideas from the Europeans. Germany is one of the countries in Europe which is going in for the solar energy. At the same time, they are not giving importance to the nuclear energy. They are even banning the nuclear energy. I don't say that the nuclear energy is not necessary. We need it for the purpose of industrial growth. But for the purpose of agricultural growth and for the rural areas, solar energy is very suitable and it has to be fully utilised for that purpose.

Solar thermal energy is also another concept. Sun light is focussed on to an absorber tube which keeps up to a very high temperature. Another system is also coming up, that is, heating of the oil. Synthetic oil is now generated, and it will be heated and it will give 400 degree centigrade heat. Through that, the energy is now taken away.

Similarly, a lot of research is going on. We have to utilise our own intelligence for this purpose to come out with more new inventions. Similarly, I would like to concentrate on the wind energy. Take for instance, China. They calculate that from their own country, they can have 6.08 trillion kilowatt of power per year through this wind energy alone. They have got the calculation that land wind energy volume will be 4.2 billion kilowatt. The exploitable capacity is 300 million kilowatt. Offshore wind energy will be 750 million kilowatt. When they are thinking that their industrial need and agricultural need and also the peoples' need can be satisfied by these systems, why not we think about it. In South India, more so, in Kanyakumari district, the wind energy is one of the projects taken up by the multinational companies also and so much of energy is being produced by them. They are selling it for multiple amounts to the State Electricity Boards. Similarly, when we are taking up the issue of the agriculturists, we used to say that the sugarcane price should be increased because as a by-product, the molasses and the products which are utilised for the purpose of electricity generation, in multiple terms, that is again sold to the Electricity Department. Therefore, all these things can be done by ordinary people. It has to be a mass upsurge in India to have the power being generated by everybody and not by the Government alone. It should not be a task for the Government, it should be a task for the entire population of India. Thank you very much.

श्री एस.एस. अहलवालिया (झारखंड) : उपसभापति जी, मैं अपने विद्वान मित्र श्री विजय जवाहरलाल दर्डा जी द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लोगों ने जो आंकड़े बताए हैं, लेकिन मैं आंकड़ों पर नहीं जाता हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि हमारे यहां कुछ power consumption necessity based है, कुछ लगजरी है, कुछ डोमेस्टिक है और उस necessity based में कुछ infrastructure भी है। मसलन, हमारा देश एक ग्रामीण प्रधान देश है, जहां किसानों को बिजली चाहिए। शायद बिजली की जरूरत न पड़ती, अगर नहरें होती और irrigation system अच्छा होता, तो शायद किसानों को उतनी बिजली की जरूरत नहीं पड़ती,

जितनी कि आज पड़ रही है। जिन इलाकों में नहरे हैं, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है, वहां आदमी नाली काट कर भी पानी अपने खेतों तक पहुंचा लेता है, पर यहां पर पंप की योजना है, इसलिए यहां पर बिजली की जरूरत पड़ती है। इसी कारण से कुछ-कुछ राज्य मुफ्त में भी बिजली देती है, unmetered बिजली देती है, इसमें कितनी बिजली जा रही है, यह भी उसको पता नहीं रहता है। दूसरा, हमारे रेलवे को बिजली लगती है, बंदरगाहों को बिजली लगती है, airports को बिजली लगती है तथा hospitals को बिजली लगती है। जहां पर जरूरत है, वहां पर कट नहीं किया जा सकता है। यदि वहां पर कट करेंगे, तो सारा देश रुक जाएगा। इसमें domestic वाले मरते हैं, जो घरेलू काम में बिजली का प्रयोग करते हैं। Small-scale industry वाला मरता है और जिसके पास अपना captive power plant नहीं है तथा captive power back-up नहीं है, वह suffer करता है।

महोदय, हमारे प्राक्तन राष्ट्रपति डा. कलाम साहब ने कहा था कि हम rural areas को अर्बन एरिया की facility provide करें। हम वह provide तभी कर सकते हैं, जब कि वहां बिजली पहुंचे। बिजली भी कई तरह की है, पर उन कई तरह की बिजली में से दो तरह की बिजली को माना गया है। एक तरह की बिजली वह है, जो carbon emissions produce करती है और दूसरी तरह की बिजली वह है, जो 'Green Energy' के नाम पर जानी जाती है।

महोदय, हमारा देश विश्व का तीसरा बड़ा देश है, जहां सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। पर, दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारा कोयला low ash नहीं है, उसकी calorific value उतनी नहीं है, जितनी एक थर्मल पॉवर स्टेशन को चलाने के लिए आवश्यक होती है। इस कारण से हमें थर्मल पॉवर स्टेशन को चलाने के लिए low ash तथा अच्छी calorific value वाला कोयला बाहर से import करना पड़ता है। Import करने का मतलब यह है कि हमारी विदेशी मुद्रा का गमन होना, आगमन नहीं, बल्कि गमन होना अर्थात् हमारी विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। पर, अभी United Nations की "Global Warming" पर जो रिपोर्ट आई है। बहुत दिनों से ऐसा माना जा रहा है कि जो थर्मल पॉवर स्टेशन्स हैं, इनमें इस तरह का technological development किया जाए ताकि इनसे कम pollution हो, इसकी व्यवस्था करें। उनकी pollution इसलिए कम करनी है, क्योंकि यह जो धुआ निकलता है, वह जो carbon emissions हो रहा है, यह ultimately, global warming का कारण बन रहा है। इस महीने में बारिश होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। किसान धान लगाने के लिए बैठा हुआ है। वह रोज उम्मीद करता है कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बिजली का उत्पादन है। हमें बिजली चाहिए भी, परंतु बिजली चाहने पर उसका बुरा असर भी है, जैसे antibiotic खाने पर बीमारी मरती भी है तथा दबती भी है, किन्तु उसका side effect भी है। तो वैसे ही इस luxury की, इस necessity की और इस जरूरत की साथ में और बीमारियां भी हैं और उन बीमारियों में सबसे बड़ी बीमारी है - ग्लोबल वार्मिंग। उस ग्लोबल वार्मिंग से निजात पाने के लिए green energy की या green energy produce करने की बात सोची गई। जब बड़े स्तर पर हम सोचने लगते हैं, तो पिछले वर्ष हमने Indo-US Nuclear Deal पर फैसला किया और उस फैसले के साथ हमें यह सोचना पड़ता है कि यूरेनियम और प्लूटोनियम, जो हमारे पास बहुत कम है - यूरेनियम की खानें मेघालय में और झारखंड में हैं, पर वह उतना purified यूरेनियम नहीं है कि उसका हम commercial exploitation करके उसके आधार पर एक या दो न्यूक्लीयर प्लांट चला सकें। हमें उसके लिए टेक्नालॉजी भी विदेश से लेनी है और raw material भी विदेश से लेना है। Green energy आएगी और हमने एक विभ्रान्ति ऐसी पैदा कर दी कि लोग कहने लगे,

पंजाबी में यह समझाने लगा कि "ओ बिजली आएगी न जिस वेल्ले, तो लट्टू बुझेगाई नई" मतलब जो बल्ब है, वह बुझेगा ही नहीं, वह जलता ही रहेगा और बिजली की खपत भी नहीं होगी। ऐसा समझाया लोगों को, किंतु ऐसा नहीं है। बिजली जब पैदा होगी तो उसकी खपत होगी। खपत होगी, तो उसकी आपूर्ति के लिए और ज्यादा बिजली पैदा करनी पड़ेगी।

महोदय, हाइड्रो प्लांट के बारे में हमारे सपने हैं। जब भाखड़ा नंगल बना और भाखड़ा नंगल में जब बिजली पैदा होने लगी, तो बहुत तरह की विभ्रान्ति उस वक्त भी पैदा की गई। कुछ नेता तो ऐसा कहने लगे कि अरे भाई, बिजली में से तो energy निकाल ली गई है और इस energy निकली हुई बिजली का पानी खेतों में डाला जाएगा, तो जो गेहूं पैदा होगा, उस गेहूं में energy नहीं रहेगी। ऐसा प्रचार करके बहुत लोग चुनाव जीतते रहे। यह विभ्रान्ति है। जब हम विकास की तरफ जाते हैं, तो विकास के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। उस सदन में हमारे हरियाणा के एक एम.पी. दो बार चुनाव इसी मुद्दे पर जीतते रहे। मणिराम बागड़ी जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका यही भाषण होता था कि जो गेहूं पैदा होगा, उस गेहूं में शक्ति ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें से तो भाखड़ा नंगल ने energy निकाल ली, यह तो पन-बिजली है। तो अब इस बार हमें महसूस हो रहा है कि भाखड़ा नंगल में जब पानी का स्तर गिर रहा है, तो भाखड़ा से जब बिजली पैदा नहीं होगी, तो उससे साथ लगे हुए राज्य affected होंगे। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब - सब affected होंगे। हिमाचल में, मेरे ख्याल से हाइड्रो का एक प्लांट है "झाखड़ी प्लांट" - वहां जो पानी है, वह तिब्बत से आता है। तिब्बत में चाइनीज ने एक बहुत बड़ा लेक बना लिया और पिछले दिनों एक बहुत बड़ी न्यूज हुई, इंटरनेशनल न्यूज हुई कि they are creating a water bomb, कि अगर उस लेक का पानी छोड़ दिया, तो हमारा जो डैम है, वह बह जाएगा। इस तरह एक panic की situation पैदा हो गई। उसी तरह हमारे उत्तरांचल में जब डैम बनने लगे, तो बहुत विरोध हुआ। जब सरदार सरोवर डैम बनने लगा, तब विरोध हुआ। हमारी कृष्णा और कावेरी पर जब डैम बनने लगे, तो वहां विरोध हुआ। विकास की तरफ जब भी आप जाएंगे और green energy पैदा करना चाहेंगे, थर्मल से हटकर, तो विरोध होंगे, इसलिए उसका ध्यान रखने की जरूरत है और उसके लिए जागरूकता पहुंचाने की जरूरत है कि अगर हम कोयले से बिजली पैदा करते हैं, तो उससे क्या नुकसान है और अगर पानी से बिजली पैदा करते हैं, तो उसके क्या फायदे हैं? वे फायदे वायुमंडल पर हैं, वातावरण पर हैं और साथ में जब एक डैम बनता है, तो उसके साथ canal system भी बन सकता है और irrigation में हमें मदद मिल सकती है। पर जिस तरह से glaciers की संख्या में कमी आ रही है, जिस तरह से glaciers समय से पहले पिघल रहे हैं, glaciers जम नहीं रहे हैं, पानी ऊपर से नीचे से आने की संभावनाएं कम हो रही हैं, उस स्थिति में hydro power पर हम कितने निर्भर रहेंगे और क्या कर सकेंगे, यह भी हमारे लिए सोचने का विषय है। यह बहुत बड़ा विषय है।

महोदय, जो Natural gas based power plant है, इसमें भी pollution है। खासकर नॉर्थ ईस्ट में असम में,

नागालैंड में, त्रिपुरा में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। आजकल बड़े प्लांट न लगाकर, छोट-छोटे प्लांट लगाकर अगर पांच, दस या बीस गांवों को बिजली दी जा सकती है तो उसकी शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि जब आप बड़े प्लांट लगाते हैं तो आपको distribution और transmission losses भी बढ़ते जाते हैं, theft की संभावना ज्यादा रहती है लेकिन जहां-जहां wells में आपको natural gas मिली है, वहां से अगर आप connectivity देकर प्लांट लगाएं और गांवों को feed करें तो वह बेहतर होगा। महोदय, आज से 15-20 साल पहले हमने solar cooker देखा। अब आपने लोगों से कह दिया कि आप छतों पर solar heater लगा लीजिए। सोलर लाइटें आ गई हैं, गांवों में, community centres में या street lights में भी सोलर का इतना प्रचलन चल पड़ा है। सर, विदेशों में solar farming हो रही है। वे धूप देखने के लिए हवाई जहाज पर चढ़कर छुट्टियां मनाने जाते हैं। धूप को महसूस करने के लिए, sunbath करने के लिए वे लोग कितने खर्च करते हैं। हमारे यहां तो sunbath रोज ही हो जाता है। सूर्य प्रणाम से शुरू करके शाम तक sunbath ही होता रहता है। अगर पूरे देश की मैपिंग करके, जहां पर सूर्य का पूरा प्रभाव रहता है, जैसे नागपुर मंत्री महोदय का राज्य है, वहां पर अच्छी धूप निकलती है, अच्छी गर्मी रहती है। Solar Farming का concept हमने पूरी तरह से commercially exploit नहीं किया है, कहीं-कहीं हम लोगों ने शुरू की है। जैसे आपने wind farm लगाया। Wind farm विद्युत उत्पादन के मकसद से कोई नहीं लगा रहा है। मैं जब वह लिस्ट पढ़ता हूँ कि किस-किसने wind farm लगाया है तो मुझे हंसी आती है कि इन्हें विद्युत उत्पादन से कुछ लेना-देना नहीं है। इन्होंने income tax बचाने के लिए wind farm लगाए हुए हैं। मैं एक बार त्रिवेन्द्रम से तिरुनलवेली जा रहा था। जिधर से रास्ता कन्याकुमारी को जाता है, वहां से बाईं तरफ तिरुनलवेली जाने के लिए घूम जाइए। मैं ज्यों ही तिरुनलवेली के अंदर घुसा तो वहां पर मैंने बड़े-बड़े wind farm देखे। उन्हें देखकर मेरी तबीयत हरी हो गयी कि इतने wind farm लगे हैं। जाने के वक्त तो मैंने उन्हें नहीं देखा, आते वक्त मैंने वहां रुककर बोर्ड पढ़ने शुरू किए कि ये wind farm किस-किस कम्पनी के हैं। उन कम्पनियों को बिजली पैदा करने से कुछ लेना-देना नहीं था। वहां पर कुछ wind farm रुके हुए थे और कुछ चल रहे थे। भूत की तरह बहुत ऊंचे-ऊंचे wind farm खड़े हुए हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ रुके हुए हैं लेकिन income tax की फाइल में तो वे लिख रहे हैं कि हमारे इतने wind farm चल रहे हैं।

Tamil Nadu State Electricity Board उतनी wind power खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है यह irrelevant है। आप देखिए कि western countries में लोगों ने अपने घर में पानी की व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए, यहां तक कि अगर उन्हें कुएं से पानी भी निकालना है तो उन्होंने wind energy लगायी हुई है। गांव-देहात में, जहां पर बिजली नहीं है, उन्होंने wind energy लगायी हुई है और उस wind energy से वे अपने घर का सारा काम कर लेते हैं। अगर हम इन छोटी-छोटी चीजों पर भी ध्यान दें तो शायद हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पॉवर मिनिस्टर का एक एडवार्टाइजमेंट निकलता है। उसमें लिखा होता है कि जब आपको बिजली का उपयोग नहीं करना है तो बत्ती बंद करके अगर पॉवर बचाएंगे तो वह विद्युत उत्पादन के बराबर है। यह आप लिखते हैं। किन्तु कभी आपने सोचा है कि हेयर ड्रायर की जो टेक्नोलॉजी है, चाहे रेजर टेक्नोलॉजी है या छोटी-छोटी चीजें, जिसमें इतनी पावर की जरूरत नहीं है, उसमें भी हमने पूरी ताकत से पॉवर दिया हुआ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अभाव है? हमारे फ्रिज, हमारे एयरकंडीशनर्स, हमारे माइक्रो ओवन तथा घर के जो अन्य एप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे वह आयरन प्रेस हो, चाहे हमारा टेलीविजन हो, चाहे हमारा कम्प्यूटर हो, चाहे हमारा प्रिंटर हो, ये सारी चीजें हैं, इन सब में पॉवर सेव करने के लिए इनको पॉवर एफिसिएंट वाले बनाए जा सकते हैं। आप कभी नापकर देख लीजिएगा।

आपके मोबाइल फोन को नोकिया एक चार्जर देता है। इसके अलावा बाजार में चाइनीज चार्जर भी मिलता है। साथ में मीटर भी लगा दीजिए। आप देखेंगे कि नोकिया का चार्जर किस स्पीड से जा रहा है और दूसरा किस स्पीड से ले जा रहा है और कितना पॉवर कंज्यूम कर रहा है। जो घटिया किस्म की चीजें हैं तथा टेक्नोलॉजी में जो चीजें डवलप्ड नहीं हैं, यह इसलिए मैं आपको मोबाइल चार्जर का एक छोटा उदाहरण आपको दे रहा हूँ, परन्तु मैं वैसे ही बोलता हूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से प्रयोग नहीं की गई है, उसमें ज्यादा ताकत लग रही है, ज्यादा पॉवर का कंजम्पशन हो रहा है, हमारे पॉवर के कंजम्पशन को कम करना है, रोकना नहीं है कि आप कंज्यूम मत करो। उनको देना है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल सकता हो। जैसे कभी जमाना था कि आपका टेबल फैन स्टील का, कॉस्ट आयरन का हुआ करता था तथा उसके ब्लेड कॉस्ट एल्यूमिनियम के होते थे। उस ब्लेड को घुमाने के लिए पंखे की मोटर की जो ताकत लगती थी, आज वह प्लास्टिक का ब्लेड हो गया, जिसके कारण अब कम ताकत लगती है तथा पहले से ज्यादा स्पीड से घूमता है। उसी तरह से अगर हमारी मशीनें, हमारे घर के एप्लॉएंसज इसी तरह के हों, क्योंकि से चीजें कम नहीं हैं और पॉवर का डॉमैस्टिक कंजम्पशन 25 से लेकर 35 परसेंट ऑफ दि टोटल प्रोडक्शन है, उसमें अगर हम इन चीजों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कम करें, उसकी बराबरी होती है कि हमने इतना प्रोड्यूस किया। जो बचाएंगे उतना हमने प्रोड्यूस किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे विद्वान मित्र श्री दर्डा जी ने एक अच्छी पहल की और एक अच्छी चीज लाए।

मंत्री महोदय को मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता था कि जब हम विदेशों में जाते हैं और वहां देखते हैं कि 110 वोल्टेज पर भी बहुत सारी चीजें चलती हैं परन्तु हमारे यहां 220 के नीचे कोई चीज नहीं चलती है। मैं कोई टेक्नीकल आदमी नहीं हूँ। पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह वोल्टेज चेंज करने से जो 110 से चल सकती हो, उसके लिए 220 का बिजली प्रयोग करना सही है या नहीं है, क्योंकि हम घर पर देखते हैं कि एयर कंडीशनर चलाने के लिए 440 वाला बड़ा प्लग लगा रहता है तथा रेडियो व टी.वी. चलाने के लिए 220 वाला लगा रहता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो 110 से भी चल सकती हैं। तो ऐसा परिवर्तन लाने से अगर हमें बिजली में बचत होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो ऐसा टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन भी हमें लाना चाहिए, क्योंकि यह सारे विश्व में है, हमारे यहां नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कोई कारण मुझको नहीं मिला है। इसके लिए कंवर्टर मिलते हैं कि आप कंवर्ट कर लीजिए। इसको ऊपर नीचे करने के लिए क्या जरूरत है, स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए कंवर्टर मिल जाते हैं। किन्तु इसके लिए क्या जरूरत है, वह जरा देखने की जरूरत है।

महोदय, मेरा यही कहना है कि हम यूरेनियम, प्लेटेनियम का तो सपना देखें, किन्तु जहां तक थोरियम की बात है, हमारे देश में इतना थोरियम उपलब्ध है और हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने थोरियम से बिजली का उत्पादन करने के बारे में अपने बहुत सारे आविष्कार कर लिए हैं। हमें थोरियम के बारे में तब पता चला जब केरल के beach से एक जहाज बालू ले जाता था। हमें इसके बारे में पहले से पता ही नहीं था, हमें अभी बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है। भारत में क्या-क्या सम्पदा है, हमें उसके बारे में पता नहीं है। केरल के beach पर एक खाली पानी का जहाज आता था, वह बालू लाद कर ले जाता था। बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा, तब पता लगाया गया कि वह कहाँ जाता है। पता चला कि वह जापान जाता है। यह भी पता लगाने की कोशिश की गई कि वे बालू का क्या करते हैं? क्योंकि बालू की वहां कमी नहीं है, चारों तरफ coast है, उनको क्यों बालू चाहिए? इसके बारे में पता चला कि इसमें कोई शक्ति है। उस शक्ति को वैज्ञानिकों ने देखा कि वह थोरियम है। उस थोरियम से बिजली का उत्पादन किया जा

सकता है। हमारी सम्पदा नदियों के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से असीम है, उसकी अभी भी गवेषणा करने की जरूरत है। हम समुद्र के किनारे टाइडल वेव से एनर्जी पैदा करने की सोचते हैं। उसके बारे में भी आविष्कार हुए हैं। समुद्र के किनारे गांव बसे हुए हैं, coastal area में लगे रहते हैं, वहां पर टाइडल एनर्जी प्रॉड्यूस की जा सकती है। इस पर मद्रास में चेन्नई के पास काफी रिसर्च हुआ है, वहां पर जो research laboratory है, उसने काफी काम किया है। जैसे हम सोलर एनर्जी के बारे में सोचते हैं, जैसे हम हाइड्रल एनर्जी के बारे में सोचते हैं, इसी तरह से हमें टाइडल एनर्जी के बारे में सोचना चाहिए। अगर इन सारी चीजों को देखा जाए, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। हमें आने वाले दिनों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उन मुसीबतों से बचने के लिए हमें नये-नये प्राकृतिक संसाधन ढूँढने पड़ेंगे, जिनके माध्यम से हम बिजली पैदा कर सकेंगे। आजकल हमारे घर ऐसे बने हुए हैं कि सुबह sun rise होने के बाद भी, हमें कमरे में बत्ती जलाकर कमरे में देखना पड़ता है। ऐसे घरों का निर्माण होना चाहिए, जिनमें हवा, पानी और रोशनी, तीनों उपलब्ध हो सकें। इस तरह के मकान बनने चाहिए, जो गर्मी में तपे नहीं, क्योंकि तपिश के कारण उस कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशन की ताकत लगती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारे घरों के डिजाइन चेज होने चाहिए, ताकि जितना हमारी बिजली का उत्पादन हो रहा है, उसी में हम अपनी खपत पूरी कर सकें। यही कहकर, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am very happy that you have given me this opportunity to join the very powerful voice of my friend, Shri Vijay Darda, on a subject which is absolutely vital for the development of our country. I am also very happy to note that, now that for the next five years we have got in place a stable Government, everybody now is thinking in terms of real solutions to real problems. I very much welcome Ahluwalia's speech and also other contributions. Let us think about the problems seriously and not bring in all kinds of extraneous situations.

We must also note that the Minister, in just a few years, has done a very signal job of increasing capacity generation. This is really a great achievement. I asked for the Table; and the Table quite categorically shows that during the last three or four years, there is a signal improvement in capacity generation. As a matter of fact, this Table also shows that for many years before that, there has been a gross neglect towards increase in power capacity. What we are facing today is the result of several decades of neglect. And, today, in just a few years' time, our Minister has tried to bring in new life into this whole programme, and he deserves the compliments for that. But then, Sir, I want to point out something which is not quite often appreciated. But, the time has now come for us for appreciating the situation. I think Dardaji started the whole speech by quoting the famous two sentences that anybody who has visited Moscow from Hotel Rossia would see "Soviet plus power is equal to Communism". There is a very big banner. Power is important all over the world, and very rarely power requires subsidy. This is one industry which should be able to generate its income, and that income should be sufficient to pay for the investments. This has been the case all over the world, Why is it not the case in our country? I am raising this issue because, as I said we are not now in a

mood of criticising or blaming this Government and that Government, but the question remains why have we not been able to increase our power generation capacity. The answer to this may be different. Maybe the people should think about it. But, I want to make a few suggestions which the Minister may kindly take into account.

There are three aspects of the power mechanism; generation, transmission and distribution. Now, distribution depends upon how much revenue you can get out of the people who are consuming that. Probably, in our country, there is a huge leakage in the distribution system. It is unfortunate, but we cannot avoid that. In a huge country like ours, there will be, again I say it is unfortunate, I am not supporting that, there will be leakages, there will be thefts, and also, several Governments either at the State level or at the Panchayat level would try to exempt specific categories of users from paying for the power. So, there is a leakage in the distribution system, which we should accept grudgingly, not permanently, but accept it within the parameters of the system.

Second is the transmission. Very rightly it was pointed out by Ahluwalia Saheb, and earlier also this question was raised by Shri Natchiappan, there is a huge transmission loss. This transmission loss is basically a technical phenomenon. Of course, when transmission loss is also due to leakages, connected with distribution, that is a different kind of issue. But, I am talking about a purely technical issue of transmission loss, and that transmission loss has to be taken care of by the Government, which is really in-charge of the transmission. The hon. Minister must take special action to see that, in the next report, the transmission losses come down in our system. Then, the question comes of generation. Sir, there is no reason why if an investor is assured of the income from power generation should not invest in power. All over the world, they do that. In fact, power industry is one of the most lucrative industries in any part of the world. The main reason for that, Sir, I might submit, is still we have not allowed the private sector a full free play in power generation. And, there is absolutely no reason for not doing that. In fact, I looked for this figure. Only 15 per cent of our power generation capacity is in the private sector, and that also has happened only in the last few years. Why? It is because if we do not allow the power generation to be done by the private sector, and if we do not allow the private sector to spend its money, energy to acquire the land, acquire the rights, acquire everything that is necessary with that and if we leave it to the Government, we are in a great trouble because, then, at every point, the Government is faced with problems which we have seen in different parts of our country. One of the reasons our Minister has not been able to move very fast on this is the question of acquisition of land, acquisition of special rights; building all these capacities is extremely difficult for the public sector. I would, therefore, submit, Sir, that let us have a new approach to power generation. Let us completely privatise it. There is a meaning to this statement.

Completely privatise means, the Government would of course help, the Government would provide the necessary support and some times, you may also support financially tax-wise. But, if any private party wants to set up a power generating capacity, it should get the full support from the Government with certain provisions.

We have some examples that people have taken charge of a coal mine in order to use coal for the power, then they are not producing the power; the coal mine is used for other purposes. I can give a number of such examples. This kind of abuses should be very specifically barred and there should be very specific action taken. But, once we have that kind of a system, then there should be only support for the private sector to do this and, the public sector, the Government, really has no place in that kind of a situation.

Sir, there is a very famous statement which is attributed to Mrs. Margaret Thatcher who said Government has no business in business. That is a false statement. That statement is not valid; it was not valid in England, it is not valid in India; it was never valid. But, there are certain businesses in which the Government has no place. For example, there is no reason why the Government should start hotels, or start some kind of a cosmetic production. This is not in Government's area. Similarly, in power, except for helping the private sector to come forward, in power generation the Government has no business.

SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Rural areas.

SHRI ARJUN KUMAR SENGUPTA: Correct! Except for areas like the rural areas, rural electrification. Because, the revenue that will come out of that will have to be ...*(Interruptions)*... Except in rural areas, to recover the cost you have to have a situation which, I do not think, our people have not yet reached. So, we may have to continue with a subsidised pricing in the rural areas for quite some time. Therefore, in rural electrification and all other areas, the Government may have to play a very major role. I, therefore, suggest to the Minister that he may like to consider it. It requires some careful thinking and working out the cost and benefit of the whole thing that the Government should involve itself in the generation of power only in the rural areas. In rest of the places, the Government should only play the role of provider of service, provider of assistance. This is, again, Mr. Natchiappan's point; he referred to the German system. If we could do that, then there is absolutely economic viability, there is no problem; namely, if the transmission lines are completely under the public sector, everybody who is generating power has the capacity or the freedom to link it to the transmission line, to the national grid at a fixed cost. Whatever the cost, that can be decided, the expenditure can be recovered. The transmission lines should be entirely in the public sector. If there are losses in the transmission, the public sector must bear it. But, the generation should continue without any kind of a stop or hold. I am requesting this thing for the Ministry to take note of; I am quite sure, they have discussed this earlier. The plan would be to have a national grid

throughout the country where anyone who can generate power can put the power to the national grid at a cost-plus price so that they are completely governed. The grid should then give power to everybody and recover money from the users. If it fails to recover money from the users because of theft, because of its inability to force them, it is the Government's responsibility, not to be condoned, but I must say it should come out in Parliament, in the Assemblies that this is the loss because of people taking away of this money. Secondly, the transmission loss, which is entirely technical, which is entirely something taken care of by the public sector companies and engineers, should also be the responsibility of the Government. Sir, this is the bare skeleton of the plan that I am talking about and I hope the Minister may be kind enough to consider it carefully. Thank you very much.

MS. MABEL REBELLO (Jharkhand): Thank you, Sir. Speakers before me have spoken, many of them about the economy of energy, technological aspect of energy, Sir. I stand here to support Vijay Darda's Resolution. I want to speak on social sector perspective of energy. Sir, electricity is like medicine for both rural and urban, and agrarian and industrial sectors. Without energy quality of life cannot be improved because I see that day in and day out in Jharkhand. Sir, Jharkhand is a mineral rich, resource rich State, but it is known for all bad reasons-bad governance, poverty, malnutrition, high infant mortality rate, high maternal mortality rate, you name and it has it. Why is it so, Sir? It is because 90 per cent, if not 90, Sir, 80 per cent of people living in rural areas even today do not have electricity. It has plenty of rainfall, 1400 millimetre of rainfall. It has plenty of coal, more than even Chhattisgarh and Orissa. But coal is not exploited to its capacity. Jharkhand has three or four thermal power plants and they are so old and antiquated that they hardly produce electricity sufficient enough to supply to its current consumers. This is a sad plight. Even Dr. Swaminathan, the scientists, who is supposed to be the man who ushered in Green Revolution in the country, says if Jharkhand, Orissa and Assam, these three States, can produce so much food for the country that not only we can supply to the whole country and all the malnourishment of the country can be eradicated but we can even supply to the world market. But what is needed is energy, Sir. People of Jharkhand and even 70 per cent of Indians who are agrarians, who are farmers, they can produce plenty of food for this country and for the world market provided we give them electricity because they are very hardworking people. We have 365 days sunlight, we have got very good soil but what we need is electricity to lift water.

If that is so, we can have not only one rain-fed crop but also definitely we can have three crops throughout the year. We can go even for off-season vegetables, fruits, and all that, Sir. Sir, somebody recently conducted a study perhaps it was Washington-based organisation known as IFTRI - and he says that out of 188 developing countries, India ranks 166th country on Hunger Index.

We are not able to produce food enough for our people. Sir, 32 crores of Indians daily go to bed without dinner and 25 crores of women and children are malnourished in our country. All this can be wiped off, everybody can have sufficient food, everybody can have sufficient nourishment provided they have electricity and we produce a lot of food. Similarly, 30 per cent of our fruits and vegetables are wasted because we do not have cold storages, because there is no cold chain, the food is getting wasted instead of going to our women and children. For all these things, the remedy is electricity. That is why I say we need to produce a lot of electricity. Not only we produce, our distribution should also be taken care of. What happens is that when some poor man puts a small wire and steals electricity, we make a big issue, "Oh, the slum man, slum dwellers are stealing electricity." But major chunk of electricity is stolen by industrialists. Big people steal. The steel producers need a lot of electricity. With the connivance of Electricity Board officials, small officials steal plenty of electricity. I know of some of the industrial houses. This is what is happening and all these needs to be contained. Otherwise, we will always have problems. Sir, the national average of irrigation is 40 per cent whereas we have got only six per cent irrigation in Jharkhand. So much of waterfall is there. We do not have dams. There is no money. Earlier Jharkhand was a colony of Bihar and after that Jharkhand has become a State. Unfortunately, there was no governance at all. There was no political stability. That is why three crores of people suffer and they migrate and we talk about Naxalism. What is Naxalism? Naxalism is a socio-economic problem because people do not have employment, particularly, the youth. Sir, last month I was in Hazaribagh and there was a meeting of a lot of people at night and I also participated and they told me, Mam, more girls are joining Naxal movement than boys. That is because of this socio-economic problem. We are not able to create employment. If there is sufficient electricity, agricultural sector can create a lot of jobs. Similarly, lot of industrial houses can come to Jharkhand and can set up a base there, start various type of industries, specially, coal based. Since we have lot of coal, steel plants can come up there but the problem again is the Naxal problem. Naxal problem is a vicious circle. Naxal problem is again connected with electricity, with power, with energy. If these things can be settled properly, yes, lot of socio-economic problems can be settled. I want to draw the attention of the hon. Minister to one or two small problems. Jharkhand has Jharsuguda mines, uranium mines and I do not know, although I have asked questions to the scientists, they say there is no leakage at all, but, still I have some apprehension that there is some leakage from these Jharsuguda Uranium mines into the water bodies of Jharkhand because Jharkhand has physically and mentally challenged children, something like more than 10 per cent and the national average is only three per cent. So, why is that in Jharkhand so many of Jharkhand children are physically and mentally challenged? There is something wrong somewhere. There is some leakage into the water bodies. I would request the hon. Minister that in Jharsuguda mines there is some leakage. You please address this problem.

Similarly, Sir, there are plenty of thermal plants in a place in Madhya Pradesh known as Singrauli. Sir, there are plenty of thermal plants and particle dust is settling all over the fields of the poor farmers and because of this the fertility of the land is going on decreasing and they are not able to produce sufficient grains. Besides that, there is particle matter in the atmosphere and because of that people are having respiratory diseases, even TB and such diseases. These PSUs, NTPC and others who are having these plants are not installing sufficient machinery to contain pollution. This is must. It should be made mandatory so that they are able to produce electricity. No pollution, no particle should come out of the factory and that the hon. Minister should ensure so that people living in and around do not have problems. Otherwise, those people will sell their land and will go all over the country as landless labourers and, again, one more socio-economic problem will be created for us. Sir, coming to alternative sources of energy, I personally feel that our country, definitely, do not have that much money to spend on research and development on Solar Photovoltaic Cells. But the rich countries should produce the technology. They are talking about the global warming, climate change, etc. They are responsible for all that. We are not responsible. Sir, 70 per cent of our people do not even light a bulb. So, we don't produce that much of pollution. It is the rich countries that are producing much pollution in the world and climate change is affecting our environment. Now, we do not have even sufficient rainfall. Our farmers are looking up and are suffering. So, I would request the hon. Minister that he should urge the developed countries in various international fora to spend sufficient money on research and development on solar energy so that Photovoltaic Cells really become cheaper and poor man can also adopt and have this technology, produce electricity for himself and for the community. This is my request.

Sir, with your permission, I wish to raise one more small issue. It is about Tripura. Sir, a State like Tripura has got plenty of gas. It does not know what to do with that. Large power plants should be installed there so that we can produce electricity in Tripura and transmit the same to the mainland. When we are thinking of one country, wherever there are resources...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We have 25 minutes. There is one more speaker and the Minister. And, then, Mr. Darda has to speak.

MS. MABEL REBELLO: So, Sir, I do not take much time. The hon. Minister should take care of it. As I said, in Tripura, gas is flowing out. I appeal that let this natural resource be used. It is a national resource. This resource should be converted into power and it should be given to the people.

Similarly, other social sector problems that accompany in producing electricity have to be addressed. We need electricity. We need energy. I am fully for that. But, whenever industrialists produce it, whether it is a PSU or the private sector, they should use sufficient pollution control machinery so that it does not affect the people in and around the plant. Thank you.

डा. प्रभा ठाकुर (राजस्थान) : धन्यवाद, उपसभापति जी। आपने टाइम एलोकेशन करके पहले ही मुझे आगाह कर दिया...

श्री उपसभापति : नहीं, यह एलोकेटेड है। इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता।

डा. प्रभा ठाकुर : सर, मैं जानती हूँ कि समय की सीमा है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं माननीय सदस्य श्री विजय जवाहरलाल दर्डा जी द्वारा प्रस्तुत इस संकल्प के समर्थन में कुछ बातें रखना चाहती हूँ।

महोदय, वैसे तो राजीव गांधी विद्युत परियोजना के तहत गांवों के विद्युतीकरण के लिए सरकार काफी काम कर रही है। अनेक गांवों का विद्युतीकरण हुआ है और हो भी रहा है। हमारे माननीय विद्युत मंत्री, श्री शिंदे साहब, स्वयं अनुभवी और योग्य हैं। वह बिजली की कमी की समस्याओं से अच्छी तरह से परिचित हैं। महोदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि जब लोक सभा में परमाणु ऊर्जा के लिए एग्रीमेंट पर चर्चा हो रही थी, तब वहां के सदस्यों ने जो कुछ बातें कहीं, राहुल जी ने भी कहीं, वह एक बहुत संवेदनशील बात थी कि आज अगर हम गांवों के बारे में सोचें, तो वहां पर बच्चे बिना बिजली के कैसे पढ़ेंगे, यह एक बड़ी जबरदस्त समस्या है। इसके साथ ही आज जबकि 8-8 महीने भयंकर गरमी पड़ती है और ऐसे समय में गांवों में गरीबों के घर में रात-रात भर लाइट न आने से एक पंखा तक नहीं चल सकता। पंखे के बिना कोई सो नहीं सकता। आज पंखा एक जरूरी आवश्यकता है। कूलर भी आज के समय में कोई लगजरी नहीं रह गया है। इसलिए मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि सौर ऊर्जा का जितना ज्यादा इसमें प्रयोग किया जा सके या फिर गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, गांवों में जो गरीब लोग रह रहे हैं, अगर उनको कुछ इस तरह का एक छोटा-सा इन्वर्टर कुछ सब्सिडाइज्ड रेट में दिया जा सके ताकि उससे कम-से-कम रात में उनके यहां बिजली के दो बल्ब जल सकें तथा दो पंखे चल सकें। इससे उन्हें राहत मिल सकेगी। आज तो किसान बरसात की कमी के कारण पानी की मार से वैसे ही परेशान हैं और कभी बरसात हो गई तो वह बिजली की कटौती से परेशान है। वह सिंचाई कैसे करेगा? इस तरह यह एक ज्वलंत समस्या है। महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है और हमारी सरकार किसानों के हित की बात करती है। इसीलिए बजट में भी, manifesto में और अपने एजेंडा में भी सरकार ने गांवों के विकास और किसानों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता दी है।

महोदय, मैं माननीय विद्युत मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि दर्डा जी के संकल्प में एक महत्वपूर्ण विषय बिजली की चोरी है। महोदय, बिजली की चोरी मिली-भगत के बिना नहीं हो सकती। इसलिए जिन कर्मचारियों, अधिकारियों व जिन उपभोक्ताओं द्वारा यह चोरी की जाती है, इसे रोकने के लिए उनके अधिकारियों को जवाबदेह बनाना जरूरी है। जब तक उनकी जवाबदेही तय नहीं होगी, उनके ऊपर मार नहीं पड़ेगी तब तक चोरी चलती रहेगी वरना अगर इस के आधार पर उन का प्रमोशन रुक जाए या उनका तबादला हो जाए या उन पर किसी तरह की penalty लग जाए तो इस देश में बिजली की चोरी बंद हो जाएगी और बाकी जरूरतमंद लोगों व किसानों को बिजली मिलेगी।

महोदय, बिजली की कटौती के लिए भी समय निश्चित होना चाहिए। यह कटौती गर्मियों में अलग समय पर हो और सर्दियों में अलग समय पर हो। अब अगर गर्मियों में भरी दोपहर में बिजली काट दी जाए तो लोग कैसे जिएंगे। महोदय, कई क्षेत्र में ऐसी गर्मी पड़ती है कि लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानवीय संवेदना के नाते कुछ ऐसा समय निश्चित करें कि सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक कटौती कर दी जाए जोकि बर्दाश्त की जा

सके। इसी तरह रात को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कटौती कर दी जाए। मैं कहूंगी कि इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए जनहित में बिजली की कटौती की जाए।

महोदय, जैसा कि अपने संकल्प में दर्ज जी ने सुझाव दिया है कि एन.टी.पी.सी., डी.वी.सी., राज्य क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जा रही समस्त विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के अंतर्गत समकालिक बनाए तथा ग्रामीण, जनजातीय तथा पहाड़ी क्षेत्रों, में इसमें जोड़ना चाहूंगी, "तथा रेगिस्तान क्षेत्रों" सहित समस्त क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करे। महोदय, आज जहां पन-चक्कियां लगायी जाती हैं, जैसा कि माननीय अहलुवालिया जी बता रहे थे कि एक भ्रांति फैला दी गई कि बिजली निकाल ली जाएगी तो पानी में शक्ति नहीं रहेगी और कृषि उपज में भी शक्ति नहीं रहेगी। इसी तरह पवन चक्कियों के बारे में भी भ्रांति फैलाई जाती है कि जहां पवन चक्कियां लगेंगी, वहां मानसून डिस्टर्ब हो जाएगा और पानी नहीं बरसेगा। इन भ्रांतियों को मिटाए जाने के लिए भी एक awareness लाए जाने की जरूरत है।

महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इस समस्या का समाधान प्राथमिक तौर पर किया जाए और आम आदमी को कम-से-कम बिजली व पंखे की सुविधा मिले, किसानों को सिंचाई की सुविधा मिले। महोदय, हमारे उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलता है, नौजवानों को रोजगार मिलता है, इसलिए वे भी फलें-फूलें और विकसित हों। इस संबंध में अमेरिका के साथ जो परमाणु करार हुआ है, यह कब से लागू होगा, यह कब से कारगर हो सकेगा, यह भी बताने का कष्ट करें? इस करार का पूरे देश ने स्वागत किया है और सभी इस करार की ओर बड़ी आशा की नजर से देख रहे हैं, अतः इस बारे में जल्द से कोई योजना बनाकर कृपया देश को बताएं ताकि हमारा देश और प्रगति करे व लोग खुशहाल रह सकें। महोदय, बिजली ही विकास की कुंजी है। बिजली शक्ति और इसके बिना कोई भी देश सबल नहीं हो सकता। महोदय, डा. मनमोहन सिंह जी ने देश के सशक्तीकरण के लिए सरकार तक को दांव पर लगा दिया था और आज वह समय आ गया है कि इस विषय को प्राथमिकता पर लेते हुए प्रस्तुत संकल्प के अनुसार सरकार कार्यवाही करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे) : उपसभापति जी, मैं मेरे साथी श्री विजय जवाहरलाल दर्डा जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही जिन साथियों, चाहे वे हमारे पक्ष के या विरोधी दल के हों, उन सभी ने इस संकल्प के बारे में जो भाष्य दिया और बिजली विभाग में जो काम चल रहा है, उस सब के बारे में सूचना दी व मुझे और ज्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया, इसलिए मैं उस सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, आज की चर्चा एक ऐसे स्तर पर पहुंची कि किस सरकार ने किस तरह का काम किया, इस बारे में टीका-टिप्पणी नहीं की गई। महोदय, यह देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और जो संकल्प हमारे दर्डा जी ने इस सदन में रखा है, मैं इस सदन के माध्यम से आप सभी को यह बताना चाहूंगा, नहीं तो मुझे भी यह मौका नहीं मिल पाता। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने केवल एक नहीं बल्कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ.... हालांकि ज़ेड तक लेकर नहीं गये, केवल तीन-चार ही बाकी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सभी बातें, जैसे बिजली के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में पूछा और सूचनाएं भी दीं। मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी वैयक्तिक प्रशंसा की। उन्होंने यह बोल कर भी मुझे सर्टिफिकेट दिया कि मैं अच्छा काम कर रहा

हूँ। आज के पत्र में भी कुछ चीजें आ गई थीं, जिनका उल्लेख श्री ज्ञान प्रकाश जी ने किया। इसके साथ ही उन्होंने यह बोला कि मेरे साथ यह अन्याय है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे बहुत कम मौके मिलते हैं जब विरोधी दल का कोई सदस्य सत्ता में रहने वाले आदमी को या मंत्री को इस प्रकार का प्रशस्ति-पत्र देता है। इसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ।

उपसभापति जी, यह बात सही है कि इस देश में बिजली की कमी है। पहले तो यह समझना चाहिए कि यह सब्जेक्ट क्या है? यह सब्जेक्ट Concurrent List में है। हमारे देश के जो राज्य हैं, उन राज्यों को बिजली-निर्माण का काम करना चाहिए। यह काम भारत सरकार का नहीं है। अर्जुन सेनगुप्ता जी कह रहे थे, मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। यह परिस्थिति हमारे देश में आज क्यों आ गई है? राज्यों ने बिजली नहीं बनाई है, इसकी वजह से यह सब नुकसान हो गया है।

उपसभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मैं तो 2006 तक आंध्र प्रदेश का गवर्नर था। उस समय दुर्दैव से बिजली मंत्रालय में हमारे साथी सईद साहब बीमार थे, इसलिए इस डिपार्टमेंट में कुछ काम होता भी था या नहीं होता था, उस वक्त का मुझे मालूम नहीं है। लेकिन, मुझे वहां से इस्तीफा देकर बुलाया गया और 2 फरवरी, 2006 को मैंने इसका कार्यभार संभाला। आज तीन साल हो गए हैं। यानी दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य में मैं यहां आ गया। उन ढाई सालों में मैंने उसको देखा तो पाया कि हमने यह प्रोजेक्ट किया था कि हम दसवें प्लान में 41,110 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करेंगे। लेकिन, मैंने यह देखा कि फरवरी, 2006 में केवल 20,000 पर काम हो रहे थे, लेकिन वहां तो डेढ़ साल आगे जाना था और केवल 20000 मेगावाट के काम हो रहे थे। जब हमने रिव्यू लिया तो 25000 मेगावाट के आर्डर्स फिर गये। यदि हम 41000 मेगावाट का टारगेट बनाते हैं और जब हमारे आर्डर्स ही 20000 के जाते हैं, तो लक्षित बिजली-उत्पादन कैसे हो सकेगा? इसलिए हम बैठे, हमने introspection किया। हमारे डिपार्टमेंट में हम सब लोगों ने introspection किया। गलती कहाँ है, हमने यह देखा।

महोदय, हमने देश को दसवीं योजना में 41000 मेगावाट बिजली देने का आश्वासन दिया था, उसमें कमी आ रही है, यह हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। विशेषतः प्रधान मंत्री जी ने मुझे जब वहां का गवर्नरशिप छोड़ कर यहां बुलाया, तो इस संबंध में मैं जरा ज्यादा ही एक्टिव था। हमने यह सोचा कि क्या-क्या गलतियाँ हैं। हमने यह देखा कि टारगेट देने में और आर्डर्स करने में gap है। हमने इसे correct किया। सर, दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, वह यह थी कि जो प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसे देखने के लिए, उसके inspection के लिए मॉनिटरिंग के लिए हमारे सिस्टम में सुधार लाना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, वह यह थी कि बिजली-निर्माण का हमारा टारगेट बहुत बढ़ रहा है। हमारी जो फैक्टरियाँ हैं, जिनके बारे में बहुत सारे सदस्यों ने बताया, उस वक्त हमारे देश में इन फैक्टरियों की बिजली के मुख्य संयंत्र बनाने की कैपेसिटी 6000 मेगावाट प्रति वर्ष की थी। जबकि हम औसतन 8000 मेगावाट बिजली क्षमता प्रतिवर्ष बनाने जा रहे थे और यहां यंत्र-सामग्री 6000 मेगावाट की है। इसलिए इन तीन चीजों पर हमने बहुत गौर से विचार किया और पहली बार 11वें प्लान में हमने 78,700 मेगावाट क्षमता का टारगेट दे दिया। तो सबसे पहली बात हमने यह करी कि जब टारगेट दे दिया तो शुरुआत में ही उसके आर्डर्स हमने किए। आज 80,000 मेगावाट बिजली क्षमता का काम एक्ज्युटिव चल रहा है, आर्डर्स प्लेस हो गए हैं। यह काम पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपके मालूमात के लिए इतना ही बताऊंगा कि 10वीं, 9वीं, और 8वीं, इन तीन पंचवर्षीय योजनाओं में, 15 साल में, हमारे देश में केवल 56,000 मेगावाट बिजली क्षमता का निर्माण हुआ था। मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, इतना ही बताना चाहता हूँ कि यह सब देखते हुए कि देश में बिजली बहुत जरूरी है और हमारे साथियों ने कहा कि हमारा

5.00 P.M.

per capita consumption 600 यूनिट है, UPA सरकारने, हमारे प्रधान मंत्री जी ने और हम सबने इस देश को आश्चर्य किया है कि हम 2012 तक 1000 यूनिट per capita consumption तक लेकर जाएंगे। जब 1000 यूनिट per capita consumption तक हम लेकर जाएंगे तो फिर बिजली का निर्माण उतना होना चाहिए और मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस समय भी हमारे कई प्रान्तों में इससे ज्यादा consumption हो रहा है। इसलिए हमने 78,700 मेगावाट का प्लान बनाया और यह बात सही है कि इसमें कुछ slippage आने वाली है, यह मुझे भी पता है क्योंकि इसमें इतनी difficulties आती हैं जैसे कहीं जमीन नहीं मिलती है, कहीं पानी की प्रॉब्लम होती है, कहीं गैस नहीं मिलती है, कहीं कोयला नहीं मिलता है, तो इससे capacity में कमी आने वाली है, लेकिन अगर टारगेट हम पहले ही कम कर देंगे, तो देश को बिजली कैसे देंगे और आज मैं इस confidence में हूँ कि 80,000 मेगावाट बिजली के निर्माण पर कार्य चल रहा है। तो जिस तरह से आज हम monitoring कर रहे हैं और मैं हर महीने बैठक लेता हूँ, अभी-अभी देश के सभी Power Ministers के साथ मैंने बैठक की है और सबसे चर्चा करके मैं अभी इस विचार पर आ गया हूँ कि कम से कम इस देश में हमारी, जो 78,700 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम 60 से 65 हजार तक ...**(व्यवधान)**... और आपने यह देखा कि उसमें captive है, captive यदि 12,000 मेगावाट का लक्ष्य और non conventional का 14,000 मेगावाट का लक्ष्य जोड़ लें तो हमारा जो टारगेट है, वह बढ़ सकता है, काफी बढ़ सकता है और जो देश को हमने आश्चर्य किया है, उसे हम पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए मैं केवल इस capacity addition पर इतना ही बोलूंगा कि एक वक्त ऐसा था कि 15 साल में हम 56,000 मेगावाट बना रहे थे और आज हम 78,700 का ध्येय बना रहे हैं और आज इस घड़ी में 15,075 मेगावाट बिजली हम 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्माण कर रहे हैं।

उपसभापति जी, मैं आपको बताऊंगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमने खाली 21,000 मेगावाट जोड़े थे। अभी हम 15,075 मेगावाट पर हैं और स्पीड पर हमारा काम आ गया है। इसलिए मालूम होना चाहिए कि बिजली मंत्रालय इस रफ्तार से आगे चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है तथा उसी विश्वास से मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि हम और भी आगे जाएंगे।

गरीबों को बिजली देने के लिए इस UPA की सरकार ने प्रोग्राम बनाया है और भारत निर्माण का प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो हमने बनाया है, उसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम है। अभी हम सभी लोग कहते थे कि देहात में बिजली नहीं है, देश की स्वतंत्रता के इतने बरस बाद भी देहात में बिजली नहीं है। हमारे यहां 1,18,000 देहात में बिजली नहीं थी और उससे भी ज्यादा हैं क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा प्रावधान बदल दिया है कि 100 पापुलेशन वाली जो झुग्गी-झोंपड़ियां या hamlets हैं, उनको भी हमने बिजली देने का प्रयास किया है।

ये जो 1,18,000 देहात हैं, उनमें से आज तक हमने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 61,990 देहातों का विद्युतीकरण कर दिया है और 86,353 का intensified electrification हो गया है, और 62 लाख BPL households electrified हो गए हैं। इसी तरह हमने 2 करोड़, 34 लाख BPL households को बिजली का कनेक्शन योजना में देना है। मैं इस सदन में इतना ही बताना चाहूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने अभी 7,000 करोड़ रुपए इस साल दिए हैं और 28,000 करोड़ Phase-I के लिए दे दिए हैं, अभी phase-II का काम बाकी है और इसका काम हम जल्दी से जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। कई साथियों ने कहा कि यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इस काम में थोड़ा सा समय और लग जाएगा, हमें यह काम 2009 में पूरा करना था,

जब 2010 के अंत तक या ज्यादा से ज्यादा 2011 के आरंभ तक यह काम हो जाएगा, क्योंकि DPR आने के बाद ये सैंक्शन देते हैं और उसके बाद काम शुरू होता है, तो 18 महीने उसमें लगते हैं। कई लोगों के मन में यह डर था कि इन लोगों को बिजली नहीं मिलेगी, हमने हर स्टेट से यह अंडरटेकिंग ले लिया है कि 6 से 8 घंटे तक इन लोगों को बिजली देनी पड़ेगी, तभी हम यह योजना वहां दे रहे हैं। 90 परसेंट यहां सब्सिडी है और इतनी बड़ी स्कीम हम पूरे देश में चला रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2011 के अंत तक हमारा यह काम पूरा हो जायेगा और देश के सभी लोगों को बिजली मिल जाएगी।

उपसभापति जी, हमारे कई साथियों ने कहा और विशेषकर दर्दा जी ने कहा कि रशिया में 1917 में जब सरकार आई, तभी बिजली पर उन्होंने जोर दिया, क्योंकि बिजली इतनी महत्वपूर्ण है। श्री सेनगुप्त जी जैसे अर्थशास्त्री ने भी जिस तरह का विचार रखा और उसको appreciate भी किया, उसका मैं समर्थन करता हूँ। यह बिजली, देश का उत्पादन बढ़ा देती है, देश का ग्रोथ रेट बढ़ा देती है और देखा जाए तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब 1,362 मेगावाट बिजली पैदा होती थी और आज हमारी installed कैपेसिटी 1 लाख, 50 हजार मेगावाट की है और हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, इस काम को हम और जोर से करना चाहते हैं, हम चीन की बात करते हैं, चीन की जो सरकार है, वहां किसी प्रकार का objection नहीं आता है, अड़गा नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कई बार चीन गया हूँ, मैं 1992 में पहली बार चीन गया था, तब मुझे बीजिंग से The Great Wall तक जाना था, उस समय उसमें ढाई घंटे लगे। बाद में मैं वर्ष 2000 में वहां गया, उस समय मेरे साथ जो लोग थे, मेरे एम.पी. मित्र थे, उन्होंने कहा कि हम The Great Wall देखने चलते हैं, मैंने कहा कि वहां जाने में ढाई घंटे लगते हैं, ढाई घंटे में जाना, ढाई घंटे में आना, आधे घंटे में देखना, अभी हमारी पास उतना वक्त नहीं है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। तो उनका जो सेक्रेटरी था, वह कह रहा था कि नहीं, वहां जाने में आधा घंटा लगता है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि कैसे, तब वह आदमी आया और उसने कहा कि अब चेज हो गया है। हम गए और आधे घंटे में वहां पहुंच गए। मैंने उनसे पूछा कि यह कैसे हो गया, पहले तो यहां आने में ढाई घंटे लगते थे? उन्होंने कहा कि एक दिन सरकार ने तय किया कि हम एक विशिष्ट दिन में एनाउंस करने वाले हैं, यहां जो भी रहने वाले हैं, वे अपना घर देखें, नहीं तो जिस दिन हम आर्डर करेंगे, उस दिन से हमने जो कैप बनाए हुए हैं, उनको वहां रहना पड़ेगा। और वह दिन आने के बाद बुल्डोजर लगाया और सब साफा किया। इसमें कोई litigation नहीं हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ। वहां कम्युनिस्ट की सरकार है। कॉम्युनिस्ट सरकार की नीति एक अलग तरह की है, लेकिन यहां पर डेमोक्रेसी है। आपने आज बहुत अच्छी बात की है। आपने आज environment की बात की है। आप हिमालय की बात कर रहे थे। मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे साथी ने बहुत अच्छी तरह से श्री बागड़ी जी का उदाहरण देकर बताया है। अभी-अभी की बात है, गंगोत्री पर छह सौ मेगावाट का एक प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पर लोग आंदोलन पर बैठे, आई.आई.टी. के लोग बैठे। इस घटना से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन मुझे उन लोगों को सुनना पड़ा। उस प्रोजेक्ट को बीच में स्टे देना पड़ा। मैं आपको क्या कहूँ, अहलुवालिया जी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप वह भूले नहीं हैं। यह जो misunderstanding है, गंगोत्री माँ की शुद्धता देने की जो एक भूमिका है, इस तरह से कभी-कभी श्रद्धा स्थान इस तरह से जुड़ाए जाते हैं, तो इससे हम लोगों को भी बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए हमें पानी का flow देने के लिए उस प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन कम करना पड़ रहा है, क्योंकि हम श्रद्धा के साथ खेलना नहीं चाहते हैं। अपने बहुत अच्छी बात की है, क्योंकि वहां पर बैठकर श्री बागड़ी जी के बारे में बोलना बहुत दिक्कत की

बात होती है। यहां से बागड़ी जी के बारे में अहलुवालिया बोल सकते हैं...(व्यवधान)...। इसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम एक तरफ technology के लिए भाग रहे हैं, 21वीं सदी की नई भूमिका हम देख रहे हैं और दूसरी तरफ जब हम 18वीं सदी की बात करेंगे, तो यह कैसे होगा? आज हमें उसी रफ्तार से चलना होगा, इसलिए मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ।

उपसभापति महोदय, मैं "बिजली बचाओ" के बारे में बार-बार कहता हूँ कि बटन आदि बंद करके जाओ। उन्होंने टी.वी. पर मुझे बोलते हुए सुना होगा। यह बहुत अच्छा है कि एक अहलुवालिया जैसा हमारा साथी सुनता है, तो इसका मतलब है कि देश के बहुत लोग सुन रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है। हमने यह जो योजना बनाई है कि "power saved is power generated" यह avoided capacity है। आज हमारे bureau of energy की जो standard and labelling है, आपने रेफ्रिजरेटर की बात की, एयर कंडीशन की बात की, अभी हमने 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार लेबल लगाया है, जिससे कम electricity consumption होती है। इसके अलावा building code आ गया है। जो बिल्डिंग बनाते हैं, उसका भी एक कोड आ गया है और उससे बिजली की बचत होती है। Energy conservation building code आ गया है। हम किसानों के लिए Agricultural DSM pump energy के माध्यम से बदल कर दे रहे हैं। इस तरह से जो हमारे Bureau of Energy Efficiency है, उसके माध्यम से जो बिजली बचत का काम चल रहा है, वर्ष 2007-08 में 3 हजार मिलियन यूनिट से ज्यादा की बिजली की बचत हो गई है। मैं Bureau of Energy Efficiency के इन लोगों का अभिनंदन करता हूँ। इस तरह का जो काम वे कर रहे हैं, वे बहुत silently काम कर रहे हैं। इस देश के 6-6 लाख, 10-10 लाख बच्चे बिजली बचत के लिए competition में द्राइंग करने आते हैं। हम समझते हैं कि इस काम के लिए वे Ambassador काम कर रहे हैं। वे अपने साथ अपने parents वगैरह को भी लेकर आते हैं। "लाइट बन्द करो", "बटन बन्द करो", इसका बहुत उपयोग हो रहा है। यह काम इस तरह से भी हो रहा है।

उपसभापति महोदय, मैं APDRP के बारे में बोलूंगा। ये जो पुराने संच है, ये भी हमें बहुत नुकसान देते हैं। बिजली की capacity addition में काम नहीं देते हैं। ये जितनी भी पुरानी हैं, इनको बदलने के लिए हमने ARDRP स्कीम की है। पहले तो यह स्कीम थी, अभी हमने दूसरी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में Restructured ARDRP स्कीम से हम काफी पैसा दे रहे हैं, जिससे देश को अच्छी पावर में मिलेगी। जो पुरानी स्कीम थी, उससे और नया टेक्नालॉजी का डाटा कलेक्ट करके उससे जुड़वाने का काम वे कर रहे हैं, ताकि हमें सब तरह का पता चल जाए कि किस तरह का क्या काम हो रहा है? अभी पीक डिमांड वगैरह में मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा कि कैपेसिटी एडिशन राज्यों ने नहीं किया है इतनी बार बोलने के बाद भी, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो इस प्रकार की चर्चा हो रही है, तो अब हमारे सभी साथी अपने-अपने प्रांतों में जाकर इसके बारे में मालूम कर लेंगे।

सर, जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में भी चर्चा हो रही है, जो आपने कहा, मैडम ने भी कहा कि इलेक्ट्रिसिटी की जो चोरी होती है, उसमें बोर्ड के ऑफिसर्स भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स से हाथ मिलाते हैं। यह बात सही है कि इसकी एक accountability होनी चाहिए, इसके लिए जो 2003 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, उसमें हमने जो कानून बनाया है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड separate होना चाहिए, रीऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ताकि ट्रांसमिशन अलग, जेनरेशन अलग और बाकी भी अलग करके accountability आएगी और पता चलेगा कि कहां नुकसान है। मैं

बताना चाहूंगा कि कितना फायदा रीऑर्गेनाइजेशन से हुआ है।

श्री उपसभापति : मंत्री जी, प्राइवेट मैम्बर्स का समय तो समाप्त हो गया है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : मैं पांच-छः मिनट में खत्म करता हूँ।

सर, रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि रीऑर्गेनाइजेशन से जो प्रॉफिट मेकिंग हुआ है, तो आंध्र प्रदेश को 341 करोड़ का फायदा हो गया है, गुजरात को 102 करोड़ का फायदा हो गया, कर्नाटक को 301 करोड़ का फायदा हो गया, महाराष्ट्र को 675 करोड़ का हो गया, उड़ीसा को 755 करोड़ का फायदा, वेस्ट बंगाल को 372 करोड़ का फायदा हो गया है। कई बार हमारे साथी कहते हैं कि unbundling करो, मैं कहता हूँ कि यह रीऑर्गेनाइजेशन है और रीऑर्गेनाइजेशन करने से इस तरह का फायदा है। उससे काफी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है और जो theft भी है, उसमें भी कंट्रोल रहता है और निगरानी रहती है। आज यह सब देखा जाएगा, तो इन सब जगहों में जो हमारी लो टेंशन (415 वोल्ट) वायर लगी हुई है, उसमें चोरी ज्यादा होती है। अब हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे 415 वोल्ट सिस्टम में चोरी करने का ज्यादा उनको कोई चांस ही नहीं होता है। यह सब सुविधा हम कर रहे हैं। जो ग्रिड है, enter signal ट्रांसमिशन ग्रिड हम कर रहे हैं और नेशनल ग्रिड की बात की है। Last year यह 17,000 मेगावाट था, आज 20,800 मेगावाट हो गया है और उसमें टोटल 37,000 मेगावाट का नेशनल ग्रिड से ट्रांसमिशन system कर रहे हैं by the end of 11th year plan, का लक्ष्य है।

उपसभापति महोदय, दिल्ली के बारे में अभी कहा गया था, तो मैं इतना ही कहूंगा कि दिल्ली की आज की highest demand है, लगभग 4400 मेगावाट और अहलुवालिया जी, आप दिल्ली में रहते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर 2010 तक इस दिल्ली में, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इसलिए हम बड़े प्रोजेक्ट्स में से बिजली देने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यह एन.टी.पी.सी. दादरी में, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट झज्जर से, मेजा से है, वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर से है और कोडरमा से है और चन्द्रपुर से है। यह सब देखा जाए तो 5000 से 6000 मेगावाट तक बिजली आने वाले अक्टूबर 2010 तक कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मिलेगी और मुझे लगता है कि इतनी बिजली होगी कि दिल्ली उसको consume नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे यहां open access है, तो दिल्ली अपनी बिजली बाहर बेच सकेगी और दिल्ली को इसका काफी फायदा हो जाएगा। यह बात सही है कि अभी फिलहाल हमारे पास दिक्कत है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा वक्त आता है कि जहां इतना करने के बाद, कितना लोड डिस्पैच सेंटर पर काम करने के बाद भी यह काम नहीं हो पाता है, लेकिन महोदय, बिजली में सुधार हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा। प्राइवेट इनवेस्टमेंट की बात हमारे माननीय साथी श्री अर्जुन कुमार सेनगुप्त जी ने कही थी। यह बहुत अच्छी बात है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो नहीं हो रहा था, the private sector capacity, at present, is 24,000 MW, that is, sixty per cent of the total capacity. While in the Tenth Plan, there was a capacity addition of only 1,930 MW in the private sector, in the Eleventh Plan, projects of over 21,000 MW are already under execution, against which 3,740 MW has already been commissioned. देखा जाए जो प्राइवेट सेक्टर में जिस तरह की capacity आ रही है, और investors आ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। इससे हमारे देश की ग्रोथ रेट बढ़ेगी या स्लो हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है। यहां पर पेपर

की रिपोर्ट के बारे में कहा गया। इससे ग्रोथ रेट बढ़ेगी। जिस तरह की चर्चा आपने की, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। महोदय, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे साथी विजय जवाहरलाल दर्डा जी एक दृष्टिमान जवान हैं। वे "वर्तमान" पत्र चलाते हैं, journalist हैं, journalist यानी वह इंसान जो बहुत दूर तक देख सकता है, लिखान देख सकता है। इस तरह से उन्होंने जो काम किया, हमारे विद्वान मित्र कह रहे थे, मैं उन्हें भी अभिनंदन देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह से उनको...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : पिलानिया जी ने कहा कि उनको doctorate भी देना है।

श्री सुशील कुमार शिन्दे : डॉक्टरेट देना है, पटना यूनिवर्सिटी उनकी है, वह देंगे। महोदय, इस देश में यह सवाल बहुत अच्छा सवाल था जो हमारे दर्डा जी आज हमारे सदन में लेकर आए। इसकी वजह से इस सदन में इस विषय पर बताने का मुझे मौका मिला, वरना मुझ पर टीका-टिप्पणी होती थी। इससे तीन साल में जो छोटा सा काम मैंने किया है, उसके बारे में मैं देश को नहीं बता पाता। आप सब लोगों ने जो सहयोग दिया, दर्डा जी ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि उनका जो resolution है, उस पर मैंने जो बात रखी, उससे कुछ समाधान हुआ होगा। सर, न्यूक्लीयर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी यूपीए सरकार, विशेषतया प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह का प्रयास किया है, उसे देश भूल नहीं सकता है। जो गरीब हमें सत्ता में लेकर आए, उनसे हमारा कमिटमेंट है लेकिन यह अरेजमेंट करने के लिए, agreement करने के लिए कुछ समय लगता है, उसके लिए मशीनरी लेने में भी समय लगता है। अहलुवालिया जी, मैं आपको assure करता हूँ - आप तो एक आध बार उधर लोक सभा में भी आएंगे। मैं कभी इधर रहता हूँ, कभी लोक सभा में जाता हूँ। अगली बार जब वे लोक सभा में आएंगे तो उनको पता चलेगा कि डा. मनमोहन सिंह जी इस देश को कितनी ऊँचाई पर लेकर गए हैं। बड़े गर्व के साथ यही अहलुवालिया जी तब उनका समर्थन करेंगे, यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपसभापति : दर्डा जी, समय नहीं है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा। मैं अपने प्रस्ताव के जरिए देश के अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री जी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। ऊर्जा हमारे देश में हर प्रकार के विकास की आवश्यकता है। अगर उपायुक्त मात्रा में विद्युत उत्पादन और वितरण नहीं होगा तो उससे हमारी economic growth प्रभावित होगी। इस बात को हमारे माननीय सदस्य पिलालिया साहब ने भी बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया। तीन विषयों पर in fact मेरा प्रस्ताव था। हमारे सीनियर मिनिस्टर शिन्दे साहब यहां पर हैं, मैं उनका आभारी हूँ। अगर फारूख अब्दुल्ला जी और श्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब भी यहां होते तो अच्छा होता। स्वयं ऊर्जा निर्माण के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण मेरे जो भाव थे, वे मैंने आपके सामने रखे। विशेष रूप से मैं उन सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ.....। जिसमें ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी थे, गंगा चरण थे। इसके अलावा राजनीति प्रसाद, डा. नाच्चीयप्पन भी थे। अहलुवालिया जी ने मुझे विद्वान कहा, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसमें अर्जुन सेनगुप्त जी ने भी भाग लिया, सुश्री रिबेलो जी ने अपनी फायरिंग वाली आवाज में सबको हिलाने का प्रयास किया। इसमें डा. प्रतिभा ठाकुर ने भी भाग लिया था। माननीय मंत्री जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि इसमें इंसेंटिव पर भी आप विचार करिए। अगर कोई समय पर काम करते हैं तो उनको इंसेंटिव देने की भी योजना होनी चाहिए, जिससे लोग समय पर काम कर सकें। आज सवाल यह भी है कि जब हम टारगेट लगातार...(व्यवधान)...

श्री सुशील कुमार शिन्दे : महोदय, मैं इनके सजेशन को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह बहुत अच्छी सजेशन है।

श्री विजय जवाहरलाल दर्डा : चूंकि आपने मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ और सदन को फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions.

SPECIAL MENTIONS

Demand for inclusivity of *Aam Admi* and percolation of envisaged benefits to target groups in Government allocations

SHRI V1JAY JAWAHARLAL DARDA (Maharashtra): Sir, from an outlay of Rs.36,000 crore in 2003-04, Government's spending on social sector and anti-poverty programmes had increased to Rs. 1,20,000 crore in 2008-09. Outcomes have not been commensurate with outlays. Therefore, the present Government has decided to make inclusive growth through overreaching objectives in the Eleventh Five Year Plan. No doubt, UN Human Development Index makes a disturbing reading as we are just two places where we were 15 years ago. This objective can only be achieved through effective participation of ground level organisations. The present bureaucratic delivery machine forecloses convergence and consumes in administrative expenses. Our beloved Prime Minister, late Shri Rajiv Gandhi, had once remarked in late 1980s that only 15 paise out of a rupee actually reaches the intended beneficiaries. This well-structured and realistic conceptualisation has now been further eroded.

This existing system needs to be replaced by participatory democratic development process. With the experience gained by implementing National Rural Employment Guarantee Scheme, the elected Panchayats, responsible to their rural-based electorates through Gram Sabhas, can be entrusted with this job as pilot project in selected areas. This project may be monitored by an independent authority once in two months as a mandatory requirement. If found feasible within a year or so, the system can be replicated extensively. Vision of new Congress-led UPA Government can thus be redeemed by launching a relentless campaign to make economic reforms central to the long-term agenda for achieving the envisaged inclusive growth.

I, therefore, urge upon the Government for taking steps for inclusivity of *aam admi* and percolation of envisaged benefits to target groups in Government allocations.

Demand to take effective measures to check the increasing number of crimes in Delhi

DR. JANARDHAN WAGHMARE (Maharashtra): Sir, Delhi is the Capital of India. But it has become a capital of crimes. Not a single day passes without a crime or two. It is a city of horrors. If you have a casual glance over the headlines in the newspapers, they indicate crimes. Delhi has lost